● सीधी, सिंगरौली,मऊगंज, रीवा एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित ● website-https://vindhyatiger.in ● epaper-https://epaper.vindhyatiger.in ● वर्ष : 37, अंक 154, पृष्ठ : 08, सीधी, शनिवार , 12 जुलाई 2025 - मूल्य : 2.00 रुपया मात्र

दैनिक समाचार पत्र

विन्ध्य टाइगर

हक की बात, बुलंदी के साथ

भाषा विवाद को लेकर बिस्वा बोले-नहीं चलेगी ब्लैकमेलिंग 5

टेस्ट के बाद ओडीआई कप्तान बनेंगे शुभमन गिल! 6

मप्र ग्रोथ कॉन्क्लेव में मिले 30 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव : डॉ. यादव

15 हजार से अधिक रोजगार के नये अवसर होंगे सृजित

प्रदेश के सभी शहरों में आयोजित करेंगे ग्रोथ कॉन्क्लेव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रियल एस्टेट आज देश का सबसे अधिक प्रोगेसिव सेक्टर है और यह सेक्टर देश के नवनिर्माण में बड़ा सहयोग दे रहा है। रियल एस्टेट के विकास में ही देश का विकास अंतर्निहित है। हम इस सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश के सभी बड़े शहरों में इसी तरह की ग्रोथ कॉन्क्लेव करके और सबको घर मुहैया कराकर नागरिकों के जीवन में खुशहाली लायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर देश की जीडीपी में अब 8.5 प्रतिशत तक योगदान दे रहा है, जो कभी मात्र 3 प्रतिशत हुआ करता था। उन्होंने गुजरात की 'गिफ्ट सिटी' का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी ही 10 स्मार्ट सिटीज़ मध्यप्रदेश में विकसित की जाएंगी। उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश में 10 लाख नए आवास तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अलग-अलग सेक्टरों के लिए विशेष ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति और नई दिशा मिलेगी।

प्रदेश के समग्र शहरी विकास और रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को इंदौर स्थित ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में 'मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025' को संबोधित कर रहे थे। इस आयोजन में उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूअल एनर्जी, आईटी आदि क्षेत्रों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे प्रदेश में 15 हजार से अधिक रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे और शहरी एवं औद्योगिक विकास को नई ऊंचाईयां प्राप्त होंगी। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के विकास के लिये 12 हजार 360 करोड़ रुपये की सौगातें भी दी। उन्होंने मुख्य रूप से जल प्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता और अधोसंरचना निर्माण के लिये 5 हजार 454 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 65 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2 हजार 799 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान भी वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा, ग्रीन फील्ड हाईवे, टाउनशिप और स्मार्ट सिटी परियोजना को बढ़ावा दिया जायेगा। कॉन्क्लेव में सर्वाधिक 12 हजार 473 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इसी तरह होटल क्षेत्र में 3 हजार 344 करोड़ रूपये, रियल एस्टेट क्षेत्र में 1812.14 करोड़ रुपये, एजुकेशन क्षेत्र में 72.45 करोड़ रूपये, रिन्यूअल एनर्जी क्षेत्र में 500 करोड़ रूपये तथा आईटी क्षेत्र में 100 करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।

यमुना पुनर्जीवन के लिए तीनों राज्यों को प्रयास करना चाहिए : शाह

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में यमुना पुनर्जीवन को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को जल प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए ऐक्शन मोड में कार्य करना चाहिए। उन्होंने यमुना की सफाई के साथ-साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता वृद्धि पर विशेष बल दिया। शाह ने 2028 तक एसटीपी की क्षमता 1500 एमजीडी तक बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, केन्द्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव सहित केन्द्र एवं दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी

शामिल हुए। दिल्ली सरकार को औद्योगिक इकाइयों से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सतत एवं प्रभावी कदम उठाने चाहिए। यमुना नदी में दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों से भी अपशिष्ट के द्वारा केमिकल आ रहा है, इसलिए इन सभी राज्यों को साथ मिलकर नदी को स्वच्छ करने के उपायों पर कार्य करना चाहिए ।

अमित शाह ने नजफगढ़ और शाहदरा के मुख्य ड्रेनों में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) को सुधारने की कार्ययोजना पर कार्य करने पर बल दिया। इसके लिए दिल्ली के दो मुख्य ड्रेन, नजफगढ़ और शाहदरा ड्रेनों की ड्रोन सर्वे कराने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नदियों को स्वच्छ करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही कोशिशों के अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। यमुना पुनर्जीवन के लिए हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों को प्रयास करना चाहिए। उनके एसटीपी से निकल रहे जल की निरंतर और निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए उन्होंने एसटीपी के आउटफ्लो की थर्ड पार्टी गुणवत्ता जांच पर बल दिया। शाह ने कहा कि दिल्ली में कई जलाशय हैं, जिनमें दिल्ली सरकार को बरसाती पानी संग्रह करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा, इन जलाशयों को विकसित करने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

महाराष्ट्र में विशेष जन सुरक्षा विधेयक पर हंगामा

विपक्ष का आरोप- सरकार जनता की आवाज दबा रही

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक जिसे जन सुरक्षा कानून के नाम से भी जाना जाता है, को ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पेश इस विधेयक का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद, खासकर शहरी नक्सलवाद को नियंत्रित करना है। हालांकि विधानसभा से पास होते ही ये विधेयक विवादों में फंस गया और विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। वहीं सरकार का दावा है कि यह कानून देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों पर कार्रवाई के लिए जरूरी है।

महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने जन सुरक्षा कानून के पारित होने पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे जनता की आवाज दबाने और सरकार की नाकामियों को छिपाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह के विधेयकों का हमेशा विरोध करेगी, क्योंकि यह जनता के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। यह विधेयक जन सुरक्षा के नाम पर लाया गया है। लेकिन, इसका मकसद सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वालों को चुप कराना है। वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार मौजूदा कानूनों का उपयोग करने के बजाय इस विधेयक के जरिए संविधान की रक्षा करने वालों को देशद्रोही ठहराना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि सरकार का असली उद्देश्य मनुस्मृति को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि किसी खास धर्म को निशाना बनाकर बयान देना गलत है। वोट जुटाने के लिए धार्मिक आधार पर समाज को बांटने की कोशिश को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एक देश एक चुनाव से नहीं होगा संविधान का उल्लंघन : पूर्व सीजेआई

नई दिल्ली। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों (सीजेआई) ने एक देश एक चुनाव मसौदे को लेकर संसदीय समिति को सुझाव दिए हैं। पूर्व सीजेआई ने समिति को बताया है कि एक देश एक चुनाव से संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। दोनों न्यायाधीशों ने प्रस्तावित कानून में चुनाव आयोग को दी गई भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को एक देश एक चुनाव विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति से बात की। सूत्रों ने बताया कि संसदीय समिति की आठवीं बैठक में दोनों न्यायविदों ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है।

बिहार के 1.11 करोड़ लोगों के खाते में पेंशन की राशि ट्रांसफर

पटना। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारवासियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि को एक करोड़ 11 लाख लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभुकों के खाते में आज 400 रुपये की जगह 1100 रुपये मिले। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए अणे मार्ग स्थित संवाद में 1227.27 करोड़ की राशि डीबीटी के जरिए हस्तांतरित कर दी। इसके बाद

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर हाल में महीने के 10 तारीख को लोगों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हर महीना की 10 तारीख को आपके खाते में 1100 रुपये चला जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने लालू राज की याद फिर से दिलाई। कहा कि 2005 से पहले क्या हुआ था? यह आपलोग सब जानते ही हैं। पहले उनलोगों ने क्या काम किया था। आपको याद दिलाते हैं हमलोगों ने ही काम किया था। पहले महिला को कोई पूछता था। पिछली सरकार ने महिलाओं के क्या किया? वह तो आपलोग जानते ही हैं। लेकिन, हमलोग आए तो महिलाओं के लिए काफी काम किया।

मुख्यमंत्री शनिवार को लाड़ली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे 26वीं किश्त

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार 12 जुलाई को ग्राम पंचायत नलवा जिला उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गैस सिलेंडर उज्जवला योजना के हितग्राहियों के खातों में जुलाई माह की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन के कालिदास अकादमी में राज्य स्तरीय निषादराज सम्मेलन में मछुआ कल्याण के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं हितलाभ का वितरण भी करेंगे।

मणिपुर में तीन उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार बरामद

इंफाल। मणिपुर में सक्रिय उग्रवादी संगठनों के खिलाफ जारी तलाशी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने राज्य के तीन जिलों से तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, गुरुवार को काकचिंग जिले के उमाथेल बाजार इलाके से प्रतिबंधित संगठन कांगलीपाक यावोल कन्ना लूप के एक सक्रिय सदस्य को पकड़ा है। इससे पहले, बुधवार को इंफाल पश्चिम जिले के मयांग इंफाल थाना क्षेत्र के ममांग लेइकाई से इसी संगठन के एक अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार किए गए इस सदस्य पर थौबल, काकचिंग और इंफाल पश्चिम जिलों में जबरन वसूली, अपहरण और नए कैडरों की भर्ती जैसे गंभीर आरोप हैं।

नेता को 75 साल की आयु में रिटायर हो जाना चाहिए : भागवत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने फिर से कहा है कि नेताओं को 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। उन्होंने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि जब आपको कोई 75 साल का होने पर बधाई देता है, तो इसका मतलब है कि आपको रुक जाना चाहिए। दूसरों को काम करने का मौका देना चाहिए।

संघ प्रमुख भागवत ने यह टिप्पणी उस समारोह में की जहां मोरोपंत पिंगले की स्मृति में एक किताब का लोकार्पण किया गया।

भागवत ने आपातकाल (1975) के बाद राजनीतिक बदलाव के दौरान पिंगले की भविष्यवाणियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब चुनाव की चर्चा हुई, मोरोपंत ने कहा था कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आएं तो करीब 276 सीटों पर जीत जाएंगे और जब परिणाम आए, तो 276 सीटों पर ही जीत हुई। हालांकि, वे चुनाव परिणाम के दौरान इन चर्चाओं से दूर रहे। पिंगले ने कभी अपनी उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया। वह अपनी मुस्कुराहट से विषयों को बदल देते थे और किसी भी सम्मान समारोह में जाने से भी बचते थे। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं। ऐसे में भागवत के इस बयान से बहस छिड़ गई है। शिवसेना (उद्धव गुट) नेता संजय राउत ने कहा कि संघ प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी को यह संदेश दिया है। हालांकि, पांच साल पहले भागवत ने 75 की उम्र में सेवानिवृत्ति के अपने इस बयान पर मोदी को अपवाद बताया था। यह भी दिलचस्प है कि पिछले साल मई में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीएम मोदी 75 साल के होने के बाद भी सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले हैं। भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। शाह ने यह टिप्पणी उस समय की थी जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी सरगर्मियों के बीच 75 साल में रिटायरमेंट का शिगूफा छेड़ा था।

दिल्ली में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरी इमारत, एक शख्स की मौत

नई दिल्ली। उत्तर दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। देर रात आजाद मार्केट के पास एक इमारत भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से एक शख्स की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं। जानकारी के मुताबिक, बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सूटकेस और तीरपाल की दुकानें थी। पास ही में मेट्रो निर्माण कार्य चल रहा था। रात करीब 2 बजे इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। दुकान के नीचे खड़ा ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ है।

दिल्ली पुलिस, फायर बिग्रेड, एंबुलेंस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्य जारी है। दमकल कर्मियों ने मलबे से निकालकर 46 वर्षीय एक व्यक्ति को घायल हालत में निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उस मृत घोषित कर दिया।

भुवनेश्वर में राहुल गांधी का भाजपा पर हमला

भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में कांग्रेस के संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा महाराष्ट्र की तरह अब बिहार में चुनाव को चोरी करने की साजिश कर रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं कल बिहार में था। जिस तरह महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी की गई, उसी तरह का प्रयास बिहार में किया जा रहा है। चुनाव की चोरी के लिए चुनाव आयोग ने एक नई साजिश रची है।

नोएडा, फरीदाबाद समेत दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा

नई दिल्ली। राजधानी में मानसून ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार शाम से शुरू हुई बारिश रुक रुक कर गुरुवार सुबह तक जारी रही। आज भी नोएडा, फरीदाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार शाम 5:30 बजे से बृहस्पतिवार शाम 5:30 बजे तक 37.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 30.6 डिग्री दर्ज किया गया।

इस साल मानसून ने 29 जून को दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों को कवर किया था। दिल्ली में मानसूनी बारिश की शुरुआत दो दिन देर से हुई। हालांकि इसके बाद से राजधानी में मानसून की बारिश ज्यादातर धीमी और बिखरी हुई रही है। सामान्यत: जुलाई के महीने में दिल्ली में 209.7 मिलीमीटर बारिश होती है। पिछले साल जुलाई में 203.7 मिमी बारिश दर्ज की गई थी।

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 16 तारीख तक लगातार बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। शनिवार को भी कमोवेश मौसम को लेकर यही स्थिति बनी रहेगी।

पाकिस्तान में घुसकर नौ ठिकानों को उड़ाया : डोभाल

चेन्नई। आईआईटी मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कई विदेशी समाचार एजेंसियों ने भारत को लेकर भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी प्रकाशित की है। इसके साथ ही अजित डोभाल ने कहा कि भारत का ऑपरेशन बेहद ही सफल रहा। हमने पाकिस्तान में नौ ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें से एक भी नहीं चूका। एनएसए डोभाल ने कहा कि विदेशी प्रेस ने कहा कि पाकिस्तान ने यह किया, वो किया... आप मुझे एक भी फोटो या सबूत दिखाइए जिसमें भारत में किसी इमारत को नुकसान हुआ हो, एक कांच तक टूटा हो... उन्होंने बातें लिख दीं और छाप दीं।

उन्होंने आगे कहा कि विदेशी मीडिया द्वारा जारी की गईं सैटेलाइट तस्वीरों में 10 मई से पहले और बाद में पाकिस्तान के 13 एयरबेस दिखाए गए, चाहे वह सरगोधा हो, रहीम यार खान हो या चकलाला। मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में छापा। हममें यह क्षमता है कि अगर हम चाहें तो पाकिस्तान के एयरबेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि हमें अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र यहां

किया गया था। हमें इस बात पर गर्व है कि इसमें कितनी स्वदेशी सामग्री थी... हमने पाकिस्तान के आर-पार नौ आतंकवादी ठिकानों पर निशाना साधने का फैसला किया, ये सीमावर्ती इलाकों में नहीं थे। हम कोई भी निशाना नहीं चूके। हमने इसके अलावा कहीं और निशाना नहीं साधा। यह उस बिंदु तक सटीक था जहां हमें पता था कि कौन कहां है? पूरे ऑपरेशन में 23 मिनट लगे। आप मुझे एक भी तस्वीर बताइए जिसमें भारत की तरफ से हुआ कोई नुकसान दिखाई दे रहा हो।

एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि हम एक ऐसे देश और ऐसी सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं, जो हजार वर्षों से संकटग्रस्त, लहूलुहान और अपमानित रही है। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है... मुझे नहीं पता कि इस सभ्यता को जीवित रखने और राष्ट्र की इस धारणा को जीवित रखने के लिए उन्होंने कितने अपमान, अभाव और कष्ट सहे होंगे। राष्ट्र, राज्य से अलग होता है। भारत, एक राष्ट्र के रूप में सहस्राब्दियों से अस्तित्व में है। अब से 22 साल बाद जब हम अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे, तब आप अपने करियर के शीर्ष पर होंगे।

दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने से पहले उनकी धार्मिक पहचान की गई। इन मृतकों में अधिकांश पर्यटक शामिल थे। इसके बाद भारत ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए।

जिलें में झमाझम बारिश का आगाज

देर रात्रि से हो रही बारिश, नदी नालों में भरा लबालब पानी

धान की रोपाई में जुटे किसान, शहर के सडको की हालत बद से बदतर

सिंगरौली। जिले भर में झमाझम बारिश का आगाज बीती रात से हो रहा है। इस बारिश के चलते नदी नालों में लवालव पानी भर गया है। वही किसान धान की रोपाई के लिए जुट गए हैं। इधर जिला मुख्यालय बैढ़न शहर के हालात बद से बत्तर हो गया है। जगह-जगह नाली चौक हो गई है और लोगों के घरों में पानी घुस रहा है शहर के सड़कों के हालात की हालत खराब है।

इधर बता दे कि जिले के देवसर, चितरंगी, सरई,माड़ा सहित जिला मुख्यालय बैढ़न में बीते गुरुवार की मध्य रात्रि से झमाझम बारिश का दौर चल रहा है वही आज शुक्रवार को भी जिले भर में बारिश लगातार हो रही है इस बारिश से नदी नाले के अलावा तालाबों में पानी लबालब भर गया है। यह बारिश कई जगह आफत भी लाई है। वही झमाझम बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है जिसके चलते किसान अपनी खेती बाड़ी में जुट गए। वहीं जिले के किसान धान की रोपाई के लिए खेतों का पलेवा कर रहे हैं। इधर बताने कि बट दांत से हो रही बारिश के चलते नगर पालिका निगम क्षेत्र के कई सड़कों के हालात कितने खराब हो गए हैं कि सड़क के गड्ढे में लबालब पानी भर जाने के चलते वाहन चालकों के साथ-साथ राहगीरों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है वही बारिश के चलते शहर की कई नालियां जाम है जिसके चलते लोगों के घरों में पानी घुस रहा है।

कीचड़ में तब्दील सड़के

नगर पालिका निगम सिंगरौली क्षेत्र में अधिकांश वार्डो में सीवरेज और गैस पाइपलाइन का निर्माण कार्य चल रहा है इस निर्माण कार्य के चलते मुख्य मार्गो की सड़कों को संविदा कार के द्वारा खोद दिया गया है। वही बीती रात से हो रही झमाझम बारिश के चलते सड़क मिट्टी खुदाई के चलते कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। जिसके चलते आवा गमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई वार्डो का हालात तो इतने खराब है कि वर्षों से उक्त वार्ड में सड़क ही नहीं बनाई गई है। यही हाल वार्ड 29 का बना हुआ है। इस वार्ड के चंद्रमा टोला में कई वर्षों पहले सड़क बनाई गई थी वर्तमान में यह सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है इसके बावजूद पार्षद उक्त मोहल्ले को भूल गए।

चितरंगी में हुई मूसलाधार बारिश

बताया जाता है कि जिले के तहसील चितरंगी क्षेत्र में बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है जो अनवरत जारी है इस बारिश के चलते क्षेत्र के छोटे बड़े नाले ऊफान पर आ गए हैं। इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि अब किसान पूरी तरीके से खेती के लिए तैयार हो गये है। वहीं किसानों का कहना है कि अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो धान की रोपाई नहीं हो पाएगी क्योंकि धान के खेतों में लबालब पानी भर गया है और खेत भी उफान पर चल रहे हैं।

शासकीय विद्यालयों की हालत जर्जर, बेखबर है जिम्मेदार

जन शिक्षा केंद्र सरई के प्राथमिक शालाओं के भवनो की हालत खराब

सिंगरौली। जिले के जन शिक्षा केंद्र सरई अंतर्गत कई शासकीय प्राथमिक विद्यालयों की हालत काफी नाजुक है जो कभी भी धराशाई हो सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्लाट टोला उफरा टोला बोदरा टोला मझियान टोला खाड़ी टोला आदि विद्यालयों के भवन जीर्ण-शीर्ण हैं। जहां बच्चों को बैठाना खतरे से खाली नहीं है। शासकीय प्राथमिक शाला प्लाट टोला की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। जहां के बच्चे अपने आपको निराश्रित समझ रहे हैं। जिनका मदद करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे भी सरई क्षेत्र में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल पड़ रहा है। वैसे भी शासकीय विद्यालयों के भवन की जर्जर हालत भाजपा सरकार की नाकामी साबित कर रही है। एवं वहां पढ़ने बच्चे उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं।

विकासखंड मुख्यालय देवसर के सरई क्षेत्र में प्राथमिक शाला- उफराडोल, प्लाट टोला, बोदराटोला मझियानटोला आदि में एक भी अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध नहीं हैं। जहां के बच्चों को खुले आसमान का ही सहारा लेना पड़ता है। काबिले गौर करने की बात है कि शासन- प्रशासन इन छोटे-छोटे विद्यालयों की ओर ध्यान नहीं देती है। क्या इन विद्यालयों की सतत् निगरानी व मानिटरिंग नहीं होती?इसतरह से इन विद्यालयों के होनहारों को किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं सुलभ हो पा रही हैं। जिनके सिर पर छत भी नहीं है। जनपद शिक्षा केंद्र देवसर के अधीनस्थ जन शिक्षा केंद्र सरई के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला प्लाट टोला की दूरी मुख्यालय से महज 500 मीटर है। जिसकी भवन की हालत काफी जर्जर होने की जानकारी मिली है जिसकी पुष्टि के लिए प्लाट टोला के प्रधानाध्यापक शाला प्रभारी दीपा मिश्रा से फोन पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। जो यह साबित करती है कि प्लाट टोला के प्रभारी विद्यालयीन बच्चों के सुरक्षा ,सुविधा से कोई सरोकार नहीं रखते हैं।

कोल वाहनों के खिलाफ आप का धरना प्रदर्शन परसौना में जारी

खुटार से परसौना तक निकाली गई बाइक रैली

सिंगरौली। आज आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रतीभान प्रसाद के अगुआई में परसौना में कोल वाहनों के खिलाफ़ अनिश्चितकालीन अनशन और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वहीं बीते गुरुवार को परसौना से खुटार तक बाइक रैली निकाल कर आंदोलन के लिए जागरूक कर समर्थन प्राप्त किया। इधर आज शुक्रवार को चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का जारी है जहां कोल वाहनों के द्वारा लगातार घटनाएं कारित की जा रही है। इन सड़क दुर्घटनाओं के चलते आए दिन लोग काल के गाल में समा रहे हैं। जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है।अभिमन्यु कुमार चौधरी आम आदमी पार्टी एससी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सिंगरौली, राजेंद्र प्रसाद साकेत जिला उपाध्यक्ष एससी प्रकोष्ठ, मोहित सिंह चंदेल जिला उपाध्यक्ष यूथ विंग, प्रियांशु सिंह बघेल समाजसेवी, पवन वर्मा, संतोषी कुमार साकेत, शिव शंकर साकेत, बृजेश कुमार पनिका, उमेश कुमार बंसल, भैया लाल पनिका, सविता चौधरी, हेमंत कुमार वर्मा एवं सैकड़ो कार्यकर्ता सम्मिलित रहे।

जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक 16 जुलाई को

सिंगरौली। जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक 16 जुलाई को दोपहर 2 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। बैठक के दौरान पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा एवं एमपीआरडीसी की समीक्षा एनएच 39 की समीक्षा सड़क परिवहन एवं यातायात विभाग की समीक्षा रेलवे विभाग की समीक्षा ललितपुर से सिंगरौली रेल लाईन एवं कटनी से सिंगरौली रेल लाईन के दोहरीकरण के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास प्राधिकरण, जल मिशन, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यात्रिकी विभाग,खाद्य आपूर्ति विभाग वन विभाग सहित जिले के विकास से संबंधित विदुओ पर चर्चा उपरांत निणर्य लिए जायेगे।

भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने उठाई जनसंख्या नियंत्रण कानून की माँग

सिंगरौली। देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय के निर्देश पर शुक्रवार को जिला सिंगरौली के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता कार्यकर्ताओं के साथ सिंगरौली कलेक्ट्रेट पंहुचकर अपर कलेक्टर माइकल तिर्की को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित एक महत्वपूर्ण ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित किया। ज्ञापन में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वह शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर उसे देशभर में प्रभावी ढंग से लागू करे। पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि भारत की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 146 करोड़ को पार कर चुकी है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत है, जबकि देश के पास मात्र 2 प्रतिशत भूमि संसाधन हैं। यह स्थिति न केवल संसाधनों पर असहनीय दबाव उत्पन्न कर रही है, बल्कि बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक विषमता जैसी विकराल समस्याओं को भी जन्म दे रही है। ज्ञापन में बताया गया कि भारत में प्रतिदिन लगभग 90,000 बच्चों का जन्म होता है, जिससे वार्षिक जनसंख्या में लगभग 3 करोड़ की वृद्धि हो रही है। इसके मुकाबले सरकार पाँच वर्षों में अधिकतम दो करोड़ रोजगार ही सृजित कर पाती है। इस असमानता के चलते हर पाँच वर्ष में लगभग 10 करोड़ नए बेरोजगार देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर अतिरिक्त भार डालते हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि यही स्थिति बनी रही तो 2050 तक भारत की जनसंख्या 170 करोड़ के पार पहुँच सकती है, जो राष्ट्रीय विकास, पर्यावरणीय संतुलन एवं सामाजिक स्थिरता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सरकार ने कोई ठोस नीति नहीं अपनाई, तो जनसंख्या विस्फोट देश के भविष्य को अंधकारमय बना देगा। अत: प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया गया है कि एक मजबूत और न्यायसंगत जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द बनाया जाए और सख्ती से लागू किया जाए। इस मौके पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सचिव सत्येंद्र विश्वकर्मा, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रामबली पाल, महासचिव रामकुमार पाल, ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश शाह, अनिल शाह,जगदीश गुप्ता, रमेश प्रजापति के साथ पार्टी के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

वैढ़न का व्यवसाई रसगंडा से लापता, स्कूटी बरामद

तलाश मे जुटी सिंगरौली-छत्तीसगढ़ पुलिस

सिंगरौली। जिला मुख्यालय बैढ़न के तुलसी मार्ग निवासी कन्हैया शू सेंटर के संचालक अनिल सोनी बीते गुरुवार की सुबह तकरीबन 11 बजे छत्तीसगढ़ के बिहारपुर रसगंडा गए हुए थे। जहां अनिल का कही रता पता नहीं चल रहा है। लेकिन उनकी स्कूटी रसगंडा में मिली है। जहां बैढ़न के व्यवसायी का रसगंडा में लापता होने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है वही सिंगरौली और छत्तीसगढ़ प्रांत के बिहारपुर पुलिस तलाश में जुटी हुई है। इधर जानकारी में बता दें कि अनिल सोनी पिता जयप्रकाश सोनी उम्र 45 वर्ष निवासी तुलसी मार्ग बैढ़न बीते गुरुवार को छत्तीसगढ़ के बिहार पुर रसगंडा अपनी स्कूटी से घूमने गए हुए थे। बीती रात तक जब घर वापस नहीं लौटे तो उनके मोबाइल पर फोन किया गया। फोन नहीं उठा। फिर बंद पाया गया। जिसे परिजनों में डर सताने लगा। तत्काल इसकी सूचना अपने परिवार के लोगों को बताया गया। और सिंगरौली पुलिस की मदद ली गई। आज शुक्रवार को बैढ़न से व्यवसायी व परिवार के लोग के अलावा पुलिस बिहार पुर पहुंची। सिंगरौली और बिहारपुर पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों की सहायता से अनिल सोनी की तलाश रसगंडा मैं की जा रही है। अनिल सोनी के परिवार जनों ने बताया कि सुबह से ही लगातार बारिश होने के चलते पानी का बहाव तेज है जिसके चलते खोजने में काफी दिक्कत हो रही है। फिर भी पुलिस गोताखोरों के सहयोग से तलाश में जुटी हुई है। स्थल पर स्कूटी में चाबी लगी हुई है जो बरामद हुई है अभी तक अनिल सोनी का सुराग नहीं लग पाया है।

ईव्हीएम मशीनो का एफएलसी रेण्डमाईजेशन, कम्युनिकेशन का कार्य सम्पन्न

सिंगरौली। सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देश के परिपालन में तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र शेखर शुक्ला के आदेशानुसार पंचायतो के उप निर्वाचन 2025 पूर्वद्ध हेतु ईव्हीएम की एफ.एलसी रेण्डमाईजेशन कमिशनिंग एवं प्रबंधन के संबंध मे दिशा निर्देश जारी किया गया है।

पंचायत के उप निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पादन करने हेतु अधिकारियो एवं कर्मचारियो के मध्य कार्य विभाजन

सिंगरौली। सचिव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के परिपालन में पंचायतो के उप निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पादन कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र शेखर शुक्ला के द्वारा अधिकारियो एवं कर्मचारियो का कार्य विभाजन करते हुयें सुचारू रूप से कार्य सम्पन्न किए जाने का आदेश जारी किया गया है। विदित हो कि आकस्मिक रूप से रिक्त हुये सरपंच एवं पंच पद का उप निबाचन होना है जिसमें कुल दो पंचायतो में सरपंच पद एवं 17 पंचायतो में पंच पद का निर्वाचन होना है। जिसमें जनपद पंचायत बैढ़न के 1 पंचायत में सरपंच पद एवं 8 पंचायतो में पंच पद का उप निर्वाचन होना है। तथा जनपद पंचायत चितरंगी में 1 पंचायत में सरपंच पद एवं 4 पंचायतो में पंच पद तथा जनपद पंचायत देवसर में 4 पंचायतो में पंच पद का उप निर्वाचन होना है। जिसे मद्दे नजर रखते हुये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अधिकारियो के मध्य कार्य विभाजन किया गया है। जिसके तहत मतगणना दल का गठन करने हेतु राम लखन शुक्ला जिला परियोजना समन्वयक एवं गौरव जिला सूचना अधिकारी एनआईसी, मतदान दलो को प्रशिक्षण हेतु एसबी सिंह जिला शिक्षा अधिकारी, सख्यकी सेल हेतु उपखण्ड अधिकारी एवं समस्त रिटर्निग आफीसर,रूट चार्ट जोनल अधिकारी तथा सेक्टर मजिस्ट्रेटो की नियुक्ति हेतु उपखण्ड अधिकारी समस्त प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनो का प्रथम रेण्डमाईजेशन हेतु प्रदीप चड़ार कार्यपालन यंत्री पीआईयू, गौरव डीआईओ एवं मान सिंह जिला व्यावसायिक समन्वयक, मतदान सामंग्री एवं आकलन वितरण वापसी की व्यवस्था हेतु रिटर्निग आफीसर समस्त एवं सहायक आयुक्त जन जाति कार्य विभाग,मतदान के पूर्व मतदान दलो हेतु सामंग्री वितरण वापसी प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी समस्त रिटर्निग आफीसर समस्त, मतपत्र की व्यवस्था हेतु वरिष्ट कोषालय अधिकारी तथा रिटर्निग आफीसर समस्त, मतदान केन्द्र को की व्यवस्था हेतु उपखण्ड अधिकारी समस्त तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को जिम्मेदारी सौपी गई है।

धान का रोपा लगाने लायक हो गई खड़ौरा की सड़क

सिंगरौली। बारिश से जनपद पंचायत देवसर के खड़ौरा गांव की सड़क खेत नुमा नजर आ रही है। सड़क धान रोपने लायक हो गई है। हालत यह है कि एक किलोमीटर की सड़क से बाइक सवार या फिर पैदल आने जाने वाले लोग जान जोखीम में डालकर निकलने को मजबूर है। यहां रहने वाले लोग कई बार प्रशासन विभागों सहित जनप्रतिनिधियों से भी सड़क बनवाने की गुहार लगाई. इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई.भारी समस्या के बाद भी जन प्रतिनिधि और जिला प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। गौरतलब है कि खड़ौरा पंचायत में यह समस्या कोई आज की नहीं है बल्कि कई दशकों से है। बारिश के दिनों में गांव की सड़क खेतों में तब्दील हो जाती है। सड़क की हालात धान रोपने जैसे हो जाती है। हालांकि मिट्टी से लथपथ कीचड़ से भरे सड़क में ग्रामीणों को चलना मज़बूरी हो जाती है। वारिस के दिनों मे यहां से गांव के किसान, स्कूली बच्चों सहित लोग यहां से जाते है और किसानों को खेत तक पहुंचने में बेहद परेशानी का सामना करना पड रहा है। सूत्रों की माने तो सड़क में कई बार मुरुम के नाम पर हजारों रुपए राशि आहरण भी किया जा चुका है। इसके बाद भी सड़क कीचड़ से लथपथ है पहली बारिश ने ग्राम पंचायत की सड़क की पोल खोल कर रख दी है। कीचड़ से लथपथ सड़क में आए दिन दुर्घटना होने की संभावना है। इस ओर ना शासन प्रशासन ध्यान दे रही है और ना ही जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं।

सड़क और खेत में अंतर नहीं'

बारिश के दिनों में खेत और सड़क में कोई अंतर नजर नहीं आता। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क पर धान रोपाई हो सकती है। लोगों ने कहा कि लगातार बारिश होने के बाद तो सड़क पर खेत भी नहीं बचता है. सड़क तालाब बन जाता है. ग्रामीणों ने कहा कि गांव की मुख्य सड़क होने के बावजूद भी वाहन लेकर यहां आने से लोग डरते हैं। यहां के इस रोड में सिर्फ ट्रैक्टर या बैलगाड़ी ही चल सकते है. चार पहिया और दुपहिया वाहनों को चलाना काफी मुश्किल है, देखते देखते कभी फिसल कर गिर जाते हैं।

अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला संवाहक है गुरु : विश्वामित्र

सिंगरौली। भारतीय सनातन संस्कृति में सदा से गुरुओं का स्थान सर्वोपरि रहा है गुरु ही शिक्षा के साथ साथ परमात्म तत्व का भी बोध कराता है एवं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का संवाहक भी है।उक्त आशय के विचार क्षेत्रीय विधायक विश्वामित्र पाठक ने देवसर में आयोजित गुरु पूर्णिमा समारोह में व्यक्त किए।

शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि. देवसर एवं शास.माडल उ.मा.वि.देवसर में गुरु पूर्णिमा समारोह का आयोजन सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में मां सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुरुआत हुई। विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विश्वामित्र पाठक ने कहा कि हमारी मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले सत्र से ही शासकीय विद्यालयों में दो दिवसीय गुरु पुर्णिमा समारोह का आयोजन कराया जा रहा है जिससे हम भारत की गौरवशाली संस्कृति की स्थापना और प्राचीन काल से चली आ रही गुरु की महत्ता एवं गुरुङ्कशिष्य की परंपरा से छात्र भली भांति अवगत हो सके। मुख्य अतिथि ने शिक्षा के क्षेत्र में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रकाश डाला।कार्यक्रम में विद्यालयों के प्राचार्य, सेवानिवृत्त प्राचार्यों ने भी गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यार्थियों को सायकल का वितरण, लेपटॉप योजनांतर्गत मेधावी छात्रों को प्रतीकात्मक चेक का वितरण किया गया तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत पौध रोपण भी किया गया। शासकीय माडल हायर सेकंडरी में से.नि.प्राचार्य रमाशंकर मिश्र, से नि व्याख्याता, अनुसुइया पाठक, से नि शिक्षक मो साबिर से नि प्राचार्य, मो. मेंहदी हसन अंसारी, अंतरवा प्राचार्य डॉ. शिवार्चन शुक्ल मधुर जी का साल श्रीफल से सम्मान किया गया।

इस अवसर पर प्रणव पाठक अध्यक्ष जनपद पंचायत देवसर, सुखदेव सिंह बीईओ, लाला सिंह प्राचार्य, कमलेंद्र द्विवेदी प्राचार्य, शिवार्चन शुक्ला प्राचार्य, अरुण चतुर्वेदी जिला आईटी सेल, शिवराम गुप्ता प्राचार्य, रमाशंकर मिश्रा (से.नि. प्राचार्य), अनुसुइया पाठक (से.नि. शिक्षक), मो0 साबिर (से.नि. शिक्षक), श्याम सुंदर गुप्ता, विद्यालय के शिक्षकगण, अविभावकगण, छात्रङ्कछात्राएं, गणमान्य जन उपस्थित रहे।

हर गरीब के पक्के आवास के सपने को सरकार पूरा करेगी : रीती

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों के गृह प्रवेश और स्वीकृत पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित

सीधी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत इंदौर से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा प्रथम चरण के पूर्ण हुए आवासों का गृह प्रवेश एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी द्वितीय चरण के स्वीकृत आवासों के स्वीकृति पत्र का वितरण कार्यक्रम स्थानीय मानस भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक सीधी श्रीमती रीती पाठक द्वारा प्रथम चरण के 74 हितग्राहियों के गृह प्रवेश में सांकेतिक रूप से चाबी देकर गृह प्रवेश कराया गया एवं 140 नवीन हितग्राहियों को स्वीकृत प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।

विधायक श्रीमती पाठक ने लाभान्वित हितग्राहियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हर गरीब के पक्का आवास का सपना पूरा करने का संकल्प लिया है। आज गरीबों को सपना साकार हो रहा है उन्हें आवास मिल रहा है और छुटे हुए हितग्राहियों को भी चिन्हित करके स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की दवाई की भी व्यवस्था की गई है। हर घर नल से जल, सभी को राशन, उज्ज्वला गैस, रोजगार के लिए प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है।

कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी मिनी अग्रवाल के द्वारा किया जाकर द्वितीय चरण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में नगर पालिका सीधी के वार्ड पार्षद जमुना कोल, आनंद परियानी एवं समाजसेवी पुनीत नारायण शुक्ला, पंकज पाण्डेय, सुधीर शुक्ला एवं नगर पालिका सीधी के अधिकारी/कर्मचारी बी के तिवारी,ब्रजेश सिंह, संदीप मिश्रा राकेश सिंह,प्रदीप द्विवेदी,देवेंद्र पोर्ते, ललोहर साहू, मनोज कुमार चौबे सहित आवास योजना के लाभार्थी हितग्राही उपस्थित रहे।

जिले में औसत वर्षा 418.9 मि.मी. दर्ज, सर्वाधिक वर्षा सिहावल में

सीधी। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि 11 जुलाई को सीधी जिले में 62.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। तहसील रामपुर नैकिन में 68.0 मि.मी., चुरहट में 96.0 मि.मी., गोपद बनास में 28.6 मि.मी., सिहावल में 78.2 मि.मी., बहरी में 52.0 मि.मी., मझौली में 96.0 मि.मी. और कुसमी में 20.7 मि.मी. वर्षा हुई है।

उल्लेखनीय है कि जिले में अब तक 418.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। 01 जून से 11 जुलाई तक तहसील सिहावल में सर्वाधिक वर्षा 551.2 मि.मी. दर्ज की गई है। तहसील रामपुर नैकिन में 265.0, चुरहट में 325.0, गोपद बनास में 310.0, बहरी में 463.1 मझौली में 541.0 मि.मी. और कुसमी में 476.7 मि.मी. औसत वर्षा हुई है जबकि गतवर्ष इसी अवधि में जिले में 148.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई थी। गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष 270.3 मि.मी. औसत वर्षा अधिक हुई है।

प्रतिष्ठित कम्पनियों में 300 से अधिक पदों पर की जायेगी भर्ती

जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार पाने का सुनहरा अवसर

शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली में एक दिवसीय रोजगार मेला 15 जुलाई को

मेले में स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भी दिया जायेगा मार्गदर्शन

सीधी

शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी डॉ संदीप कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन की मंशा अनुसार जिले के बेरोजगार शिक्षित युवक-युवतियों हेतु युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप के अवसर एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक संयुक्त रोजगार मेला युवा संगम आयोजित किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था और जिला उद्योग केन्द्र सीधी के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय (युवा संगम) रोजगार मेले का आयोजन 15 जुलाई 2025 मंगलवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली में किया जा रहा है।

महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ गीता भारती ने बताया कि इस रोजगार मेले में आवेदकों को कॅरियर बनाने का सुनहरे अवसर के साथ-साथ स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये लोन की प्रक्रिया बावत मार्गदर्शन भी दिया जायेगा। साथ ही रोजगार मेले में कई प्रतिष्ठित कंपनिया 300 से अधिक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रारम्भिक रूप से चयन हेतु उपस्थित रहेंगी। जिसमें लेखापाल, टीम लीडर, एचआर, सैल्स, बीपीओ, टेक्नीशियन (फिटर/इलेक्ट्रीशियन/टर्नर/कोपा). पेकर/लोडर, मार्केटिंग आदि के विभिन्न पदों हेतु आकर्षक वेतन पर रोजगार प्रदान करने हेतु कम्पनीयों के प्रतिनिधि आवेदकों के साक्षात्कार लेकर प्रारम्भिक रूप से चयन करेंगे।

उक्त मेले में 18 से 40 वर्ष के आवेदक जो कि हाईस्कूल से लेकर स्नातकोत्तर किसी भी विषय में उत्तीर्ण एवं तकनीकी योग्यता जैसे आईटीआई के आवेदक भी उक्त पदों हेतु रोजगार मेले में भाग लेकर योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार मेले में सम्मिलित होने वाले आवेदक अपनी समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ बायोडेटा की प्रतियों एवं अन्य प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड आदि के प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियों भी आवश्यक रूप से साथ लायें।

बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाईजर का प्रशिक्षण 14 जुलाई से

सीधी। संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिले के चारों विधानसभाओं 076-चुरहट, 077-सीधी, 078-सिहावल, 082-धौहनी (अ.ज.जा) में दिनांक 14.07.2025 से 16.07.2025 तक बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाईजर प्रशिक्षण उनके संबंधित विधानसभाओं में आयोजित किये जा रहे हैं। जिसमें जिले के कुल 1209 बीएलओ एवं 121 बीएलओ सुपरवाईजर को जिला स्तरीय एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जावेगा। उक्त प्रशिक्षण में मतदाता सूची पुनरीक्षण/बीएलओ एप्प एवं समय-समय पर आयोग द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में प्रशिक्षार्थियों को अवगत कराया जावेगा। जिले के चारों विधानसभाओं के अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया जा चुका है तथा प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत दण्डित की जाने की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।

कन्या महाविद्यालय में मनाया गया गुरुओं के सम्मान का पर्व गुरु पूर्णिमा

सीधी

शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम पूर्व प्राचार्य एवं हिन्दी के विद्वान डॉ सुरेन्द्र बहादुर सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य एवं प्रो ओमप्रकाश नामदेव की अध्यक्षता में मां वीणापाणि के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर एवं मुख्य अतिथि का माल्यार्पण उपरांत अंगवस्त्र एवं श्रीफल भेंटकर सम्मान के साथ प्रारंभ हुआ। गुरु की महिमा पर बोलते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि पहली पूर्ण गुरु मां होती है बाद में हम सब गुरु होते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके गुरु का परिचय करा देता है। अध्यक्ष ने माना कि हर व्यक्ति को सही मंजिल तक पहुंचाने में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने विचार रखते हुए डॉ सतेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि विश्व में एक हमारा देश है जहां हम देश को भारत माता कहते हैं। यही कारण है कि हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। डॉ नागेन्द्र सिंह ने अपने गुरुजनों को स्मरण करते हुए कहा कि हमारा अस्तित्व तभी तक है जब तक हम गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं। डॉ राजेश साहू ने गुरु को परं ब्रह्म माना। आभार प्रदर्शन डॉ प्रतिमा कौल द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा महाविद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम पर पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

राजस्व विभाग से सांठ-गांठ कर हुआ खेल

मामला ग्राम पंचायत नकवेल में जमीन नामांतरण का

सीधी। राजस्व विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती है ऐसे में जिले के चुरहट तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत नकवेल में राजस्व विभाग से सांठ- गांठ करके फर्जी तरीके से भूमि का नामांतरण करने का मामला प्रकाश में आया है। जिसमें उमेश कुमार पटेल पिता स्व. रावेन्द्र प्रसाद पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड न-13 ग्राम पंचायत नकवेल ने शपथपत्र के माध्यम से तहसील चुरहट में भूमि में किए गए बंटवारा की जांच कराते हुए नामांतरण पर रोक लगाने की मांग की है। शपथपत्र में बताया गया कि ग्राम नकवेल वार्ड-14 की आराजी खसरा क्र० 1430/2 का शपथकर्ता सहखाद्धेदार है उक्त भूमि का अवैध तरीके से गंगी देवी प्रजापति पति राममनोरथ प्रजापति के नाम से नामांतरण करा लिया गया है जिसका प्रकरण एसडीएम कार्यालय में चल रहा है। उन्होंने बताया कि राममनोरथ प्रजापति राजस्व विभाग में कार्यरत थे और जालसाज करके भूमि में अवैध तरीके नामांतरण अपने नाम करा लिए है अब उस भूमि पर अपना कब्जे कायम करने के लिए आतुर है लेकिन शपथकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि पर उसका अधिकार कायम है और उनके द्वारा कराया गया नामांतरण अवैध है।

पदोन्नति नियम 2025 के अंतर्गत पदोन्नति रोकने के लिए सपॉक्स ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सीधी। मध्यप्रदेश पदोन्नति आरक्षण अधिनियम 2002 उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने के बाद सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका के विचाराधीन होने के बावजूद मप्र शासन की मंत्री परिषद की कैबिनेट बैठक दिनांक 17.06.25 में शासकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण संबंधी नए नियम 2025 को लागू कर तत्काल पदोन्नति प्रारंभ करने का निर्देश शासन स्तर से जारी किया जा चुका है। पदोन्नति नियम 2025 से परिलक्षित होता है कि सरकार द्वारा पदोन्नति नियम 2002 के कतिपय प्रावधानों को संशोधित

किया है। लेकिन अभी भी क्रीमीलेयर को आरक्षण से बाहर करने के कोई प्रावधान संभवतः इन नियमों में नहीं हैं। उक्त नियम से भविष्य में पदोन्नति संबंधी विसंगतियां दूर होने की संभावना है किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार पदोन्नतियां 2016 से न कर इन नियमों को जारी होने की तारीख से लागू की गई है सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक संस्था इन नियमों का विरोध करती है। पदोन्नति नियम 2025 जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे अर्थात उन सेवा निवृत अधिकारी कर्मचारियों को इनसे कोई लाभ नहीं होगा जिन्हें 2016 से निरंतर अन्य करते हुए अनावश्यक रूप से पदोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया था अधिकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता वर्तमान पदक्रम सूची अनुसार रहेगी अर्थात उन्हें पदा नवत नहीं किया जाएगा जिनके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय वर्ष 2016 में पदानवत करने का आदेश दिया था नियमों में क्रिमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अनेकानेक स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नियमों में इनका प्रावधान न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे नियम वर्तमान में लागू कर सरकार पुनः इन वर्गों के साथ अन्याय कर रही है। उल्लेखनीय है कि असंवैधानिक नियम 2002 पर सरकार की सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील पर यथास्थिति के आदेश हैं। किंतु यह आदेश अनु जाति/ जनजाति वर्ग के शासकीय कर्मियों पर ही लागू होते हैं, जो असंवैधानिक नियमों के अंतर्गत पदोन्नत किए गए थे। सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मियों की पदोन्नति पर कभी भी रोक नहीं थी, किंतु सरकार ने अनारक्षित वर्ग की पदोन्नतियां विगत 9 वर्षों से रोककर अन्याय जारी रखा।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित

सीधी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मुकेश कुमार शिवहरे, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक द्वारा आज दिनांक 10.07.2025 को आधार केन्द्र के पास में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री शिवहरे द्वारा उपस्थित लोगों को असंगठित क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, गरीबी उन्मूलन योजना का प्रभावी कियान्वयन नालसा, सालसा एवं राज्य शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। श्री मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा उपस्थित लोगो को नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना, लोक अदालत योजना, बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई।

सतीश द्विवेदी को मातृशोक

सीधी। रामपुर नैकिन बघवार निवासी वरिष्ठ संविदाकार और समाज सेवी भाजपा नेता सतीश कुमार द्विवेदी की माता सावित्री द्विवेदी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

निधन का समाचार प्राप्त होते ही बघवार अंचल में शोक की लहर दौड़ गई। डॉक्टर नीरज द्विवेदी, पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा निज निवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्ति की। स्वर्गीय सावित्री द्विवेदी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गई है।

युवक पर जानलेवा हमला, जमीन विवाद को लेकर चले लाठी, डंडे और टंगी, एक गंभीर घायल

शहडोल। मप्र के शहडोल जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के कनाडी कला गांव में एक युवक पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। पीड़ित कपिलदेव गुप्ता अपनी पट्टे की वैध भूमि पर पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य करवा रहे थे, इस दौरान गांव के कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया।

पीड़ित के अनुसार हमला करने वालों में गांव के हनुमा कोल, विष्णु कोल और लालबाबू कोल शामिल हैं। तीनों ने उस पर लाठी, डंडों और टंगी से हमला किया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित कपिल के सिर, नाक और कंधे पर गहरी चोटें आई हैं। कपिल गुप्ता ने बताया, मैंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन आरोपी मुझ पर तब तक हमला करते रहे जब तक वह वहां से निकल नहीं गया। इस दौरान मोती साहू नाम का एक व्यक्ति कपिल का बैग लेकर मौके से फरार हो गया। शुरुआत में कपिल ने बैग चोरी की रिपोर्ट नहीं कराई, लेकिन बाद में स्थिति स्पष्ट होने पर उन्होंने जान से मारने का प्रयास करने और लूट की शिकायत की। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अजय बैगा ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है, उनकी तलाश की जा रही है।

समग्र आधार लिंकिंग एवं ईएसएस प्रोफाइल पूर्ण करने के निर्देश जारी

सीधी। आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल ने निर्देशित किया है कि आईएफएमआईएस में कोषालय से संबंद्ध समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अपने अधीनस्त कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों का समग्र ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत समग्र आई.डी. का आधार के साथ मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। आईएफएमआईएस अंतर्गत ईएसएस प्रोफाइल में समस्त शासकीय सेवकों के डिटेल यथा नामिनी, परिवार विवरण, ई-मेल, मोबाईल नम्बर अपडेट नहीं होने के कारण विशेष रूप से आवश्यक कारण संबंधितों का पेंशन प्रकरण, नामांकन, अनुकम्पा नियुक्ति तथा स्वत्वों के भुगतान में तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो रही है।

जमोड़ी में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित

सीधी

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मुकेश कुमार शिवहरे, श्री कपिल देव काछी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक द्वारा ग्राम जमोड़ी में जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री शिवहरे द्वारा उपस्थित लोगों को मौलिक कर्तव्य, मानव अधिकार, मध्यस्थता, नेशनल लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा, सालसा एवं राज्य शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उक्त शिविर में श्री कपिल देव काछी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा उपस्थित लोगो को नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100, निःशुल्क विधिक सहायता, गरीबी उन्मूलन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, डॉन- (नशा मुक्त भारत के लिए नशा जागरूकता और कल्याण मार्गदर्शन) योजना 2025, वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवा योजना तथा शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई साथ ही मध्यस्थता योजना के बारे में विस्तार से बताया। श्री मनीष कौशिक ने उपस्थित लोगों को पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट, पीड़ित प्रतिकर योजना, लोक अदालत योजना, बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई।

उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मुकेश कुमार शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री कपिल देव काछी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक जिला प्राधिकरण के कर्मचारीगण श्री रूपेन्द्र कुमार मिश्रा, श्री राजेश प्रताप सिंह एवं आमजन उपस्थित रहे।

संपादकीय

चुनावी मुद्दा

बिहार में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है। जिस तरह से राजधानी पटना के एक पॉश इलाके में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे सरकार के क्राइम कंट्रोल के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल यह मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है और इसका चुनावी फायदा लेने की कोशिशें भी होंगी। बिहार में अपराध हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है। करीब दो दशक की सत्ता में जेडीयू अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में यही गिनाती है कि उसने राज्य को लालू के जंगल राज से बाहर निकाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के नेता किसी भी मौके पर लालू-राबड़ी के कार्यकाल में हुए अपराधों की याद दिलाने से नहीं चूकते। लेकिन, गोपाल खेमका हत्याकांड हर सरकारी दावे पर एक सवाल की तरह है। डीएम ऑफिस के पास वारदात बताती है कि अपराधियों में पुलिस-प्रशासन का डर नहीं है, और यह भी कि संगठित अपराध फिर से सिर उठा रहा है। समस्या है कि बिहार से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तीन दिन पहले ही सीवान में तीन लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई। वहीं, पिछले महीने 10 साल की रेप विक्टिम की मौत ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया था। आरोप है कि बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिला। ऐसी हर वारदात नीतीश सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। 2005 से अभी तक, आरजेडी के बिना या उसके साथ, नीतीश जब भी सत्ता तक पहुंचे, तो क्राइम कंट्रोल के वादे के साथ। बिहार के लोगों को हमेशा यह अहसास कराया गया कि नीतीश ही अपराध पर लगाम लगा सकते हैं। सरकार अपने समर्थन में नैशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो का डेटा दिखाती है, जिसके हिसाब से अपराध के मामले में बिहार से भी ऊपर कई राज्य हैं। जेडीयू ने इस साल मई आखिर में एनसीआरबी के हवाले से बताया था कि देश मे अपराध की दर 422.2 प्रति लाख है, जबकि बिहार में 277.1 प्रति लाख। हालांकि आंकड़े पूरी सच्चाई नहीं बताते। हर अपराध जनता का भरोसा तोड़ता है। आज के समय की तस्वीर ऐसी बन रही है, जहां बिहार में अपराधी फिर से बेखौफ हो रहे हैं।

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान पर संदेह के सवालों के साथ मुखर विपक्षी दल इसके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई के साथ ही कानून विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस बीच, एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने एनडीए से दूरी बनाते हुए बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत देकर सियासी परिदृश्य को दिलचस्प बना दिया है। इन्हीं परिदृश्यों के बीच बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के फैसला लेकर चुनावी सरगर्मियों को एक नया मोड़ दे दिया है। बिहार सरकार का यह निर्णय केवल एक चुनावी रणनीति भर नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक परिवर्तन का संकेतक भी है। तय है कि इस बार के बिहार चुनाव के काफी दिलचस्प एवं हंगामेदार होंगे। सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के गहरे निहितार्थ हैं। एनडीए की नीतिश सरकार ने स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देने एवं उनके लिए सरकारी रोजगार उपलब्ध कराने के इस ब्रह्मास्त्र को दाग कर चुनावी समीकरण अपने पक्ष में कर लिये हैं।

बिहार चुनावों में महिलाओं पर दांव के निहितार्थ

(ललित गर्ग)

सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के गहरे निहितार्थ हैं। एनडीए की नीतिश सरकार ने स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देने एवं उनके लिए सरकारी रोजगार उपलब्ध कराने के इस ब्रह्मास्त्र को दाग कर चुनावी समीकरण अपने पक्ष में कर लिये हैं। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक मतदान की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दल लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, नये-नये मुद्दों को उछाला जा रहा है। गोपाल खेमका हत्याकांड हो या तंत्र मंत्र के चलते एक ही परिवार के पांच लोगों को जला देने की त्रासद घटना- नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान पर संदेह के सवालों के साथ मुखर विपक्षी दल इसके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई के साथ ही कानून विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

इस बीच, एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने एनडीए से दूरी बनाते हुए बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत देकर सियासी परिदृश्य को दिलचस्प बना दिया है। इन्हीं परिदृश्यों के बीच बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के फैसला लेकर चुनावी सरगर्मियों को एक नया मोड़ दे दिया है। बिहार सरकार का यह निर्णय केवल एक चुनावी रणनीति भर नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक परिवर्तन का संकेतक भी है। तय है कि इस बार के बिहार चुनाव के काफी दिलचस्प एवं हंगामेदार होंगे। सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के गहरे निहितार्थ हैं। एनडीए की नीतिश सरकार ने स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देने एवं उनके लिए सरकारी रोजगार उपलब्ध कराने के इस ब्रह्मास्त्र को दाग कर चुनावी समीकरण अपने पक्ष में कर लिये हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे 'महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक समाधान' बताया, क्योंकि राज्य की महिलाएँ कई चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में महिलाओं की मतदान दर पुरुषों से कहीं अधिक रही, 59.45 प्रतिशत महिलाओं ने हिस्सा लिया जबकि पुरुष केवल 53 प्रतिशत मतदान करने पहुंचे। यह आंकड़ा दिखाता है कि चुनावी जीत में महिला मतदाता कितनी निर्णायक हो सकते हैं, साफ है, सत्ता की चाबी वहां महिलाओं ने अपने हाथों में ले ली है और वे धार्मिक व जातिगत आग्रहों से अधिक लैंगिक हितों से प्रेरित हैं। बिहार उन शुरुआती राज्यों में एक है, जिसने पंचायत और स्थानीय निकायों में आधी आबादी के लिए पचास फीसदी सीटें आरक्षित की हैं। इस कदम ने यहां की स्त्रियों में जबर्दस्त राजनीतिक जागरूकता पैदा की है। चुनावों की दशा एवं दिशा बदलने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक किरदार निभाने के कारण ही हरेक राजनीतिक दल महिला वर्ग को आकर्षित करने में जुट गया है। राजद-कांग्रेस-वाम दलों का महागठबंधन 'माई-बहिन मान योजना' के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये देने का वायदा कर चुका है, तो राजद नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी और डोमिसाइल के मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में, नीतीश सरकार के इस नीतिगत दांव को समझा जा सकता है। जातिगत और स्थानीय समीकरण भुनाने के लिए निश्चित ही यह एक संगठित चाल है, जहां जाति और आवासीयता दोनों को आधार बनाया गया। यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत में शैक्षिक क्षेत्र में लैंगिक खाई लगातार सिमट रही है। बिहार की बेटियां देश के अनेक महानगरों में अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर पहचान बना चुकी हैं। सूचना क्रांति, बढ़ती अपेक्षाओं और सामंती बंधनों के ढीले पड़ते जाने के कारण अब ग्रामीण बिहार की बेटियां भी ऊंचे सपने संजो रही हैं। हाल ही में बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान यह देखा गया कि देश के विभिन्न प्रदेशों की योग्य लड़कियां इंटरव्यू देने आईं, जिनमें से अनेक ने सफलता प्राप्त की और अब बिहार के सरकारी स्कूलों में अध्यापन कर रही हैं। निस्संदेह, यह एक सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील और समावेशी समाज का प्रतीक है, जहाँ महिलाएं सीमाओं से परे जाकर अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर देखें, तो महिला सुरक्षा, सामाजिक असमानता, आवास व पारिवारिक बाधाएं, और प्रवास की मजबूरियाँ अब भी मौजूद हैं। ऐसे में यदि सरकारें योग्य महिलाओं को उनके घर के आस-पास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, तो यह न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक कदम होगा, बल्कि सामाजिक संरचना में स्थिरता और पारिवारिक सहूलियत का भी कारण बनेगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार सरकार महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए एक के बाद एक योजनाएं ला रही है।

साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, पिंक टॉयलेट, महिला पुलिस भर्ती में आरक्षण जैसे कई कदम इस सिलसिले में पहले ही उठाए जा चुके हैं। यह मान्यता कि बेटियां अब सिर्फ अपने घरों की शोभा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भागीदार हैं, नीति निर्माण में स्पष्ट झलकने लगा है। यह न केवल बिहार की महिलाओं को उनके अधिकार का अनुभव कराएगा, बल्कि बेरोजगारी से जूझते प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा के पलायन को भी रोकेगा। इस फैसले से खास तौर पर निम्न और मध्यमवर्गीय महिलाओं को फायदा होगा, जिनके लिए दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करना एक बड़ा पारिवारिक और सामाजिक संकट बन जाता है। घर के पास नौकरी मिलने से न केवल सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थायी उपस्थिति और भूमिका भी मजबूत होगी। हालांकि इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों की मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इसे नीतीश कुमार की चुनावी चाल बताया है और आरोप लगाया है कि सरकार महिलाओं की वास्तविक समस्याओं को दूर नहीं कर पा रही, बल्कि सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को उछालकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि महिला आरक्षण सही है, लेकिन रोजगार के अवसर कब हैं? सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया वर्षों से लटकी रहती है, परीक्षा की तारीखें टलती हैं, नियुक्ति पत्र देर से आते हैं, ऐसे में आरक्षण का लाभ कब और किसे मिलेगा? उनकी बातों में सच्चाई भी है, क्योंकि प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी आरक्षण की नीति। यह महिला आरक्षण अब केवल बिहार के स्थायी निवासियों अर्थात डोमिसाइल महिलाओं के लिए ही होगा।

हिंदी विरोध के जरिए राष्ट्रीय मानस पर चोट

(उमेश चतुर्वेदी)

हिंदी बोलने के लिए हिंदीभाषियों को प्रताड़ित करने वाली राजनीति का अतीत भी ऐसा ही रहा है। शिवसेना का उभार पिछली सदी के साठ के आखिरी वर्षों में मुंबई में मलयालम बोलने वालों को खिलाफ आंदोलन के बाद हुआ। इसे राजनीतिक विद्रूप ही कहेंगे कि हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार देने वाली मराठी माटी पर ही हिंदीभाषियों को अपमानित किया जा रहा है। महाराष्ट्र की धरती पर हिंदीभाषियों को अपमानित करने में राजनीति के दो चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ अपमानित करने वाली शिवसेना और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे है तो दूसरी तरफ राज्य की सत्ता है। हिंदीभाषियों को अपमानित करने वाली राजनीति का मकसद हिंदी विरोध पर मराठी मानुष की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अपना वोट बैंक मजबूत करना है तो दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष के एक हिस्से की राजनीति है, जो अपमानित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इस डर से नहीं कर रही कि कहीं इससे मराठी मानुष की धारणा कमजोर ना हो जाए और उसके जरिए उसका अपना समर्थक आधार ना खिसक जाए। राजनीति की इस चक्करघिन्नी में निम्न मध्यवर्गीय या हाशिये वाला हिंदीभाषी समुदाय ही पिस रहा है। उसका अपराध यह है कि वह महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी ना बोलकर हिंदी बोल रहा है। हिंदी बोलने के लिए हिंदीभाषियों को प्रताड़ित करने वाली राजनीति का अतीत भी ऐसा ही रहा है। शिवसेना का उभार पिछली सदी के साठ के आखिरी वर्षों में मुंबई में मलयालम बोलने वालों को खिलाफ आंदोलन के बाद हुआ। मनसे के कार्यकर्ता 2008-09 के दौरान तो केंद्रीय नौकरियों के लिए मुंबई में परीक्षाएं देने आए उत्तर भारतीय विशेषकर उत्तर प्रदेश-बिहार के छात्रों को को खुलेआम पिटते रहे। उस समय की राज्य सरकार ने इस बदसलूकी के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने से बचती रही थी और आज की सरकार का भी कुछ वैसा ही रवैया है। मराठी मानुष का बोध महाराष्ट्र में इतना गहरा है कि सरकारें चाहें जिस भी दल की हो, इस मसले पर तकरीबन एक जैसा रूख अपनाने से परहेज नहीं करतीं। भारत की संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने का विचार देने में महाराष्ट्र की हस्तियों का बड़ा योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक ने बंग-भंग के वक्त 1905 में वाराणसी की यात्रा की थी। वहां उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो कहा था, उसे महाराष्ट्र की हिंदीविरोधी राजनीति को जानना चाहिए। तिलक ने कहा था, 'निस्संदेह हिंदी ही देश की संपर्क और राजभाषा हो सकती है। लोकमान्य अकेले मराठी मानुष नहीं हैं, जिन्होंने हिंदी को लेकर यह विचार दिया। 1960 से पहले आज का गुजरात राज्य भी महाराष्ट्र

का ही हिस्सा था। 1880 में गुजराती कवि नर्मदाशंकर दवे उर्फ नर्मद कवि ने लोकमान्य से करीब चौथाई सदी पहले हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में आगे लाने का सुझाव दिया था।

हिंदी को स्थापित करने की महात्मा गांधी की कोशिशों से भला कौन इनकार कर सकता है। 1918 में गांधी जी की अध्यक्षता में हुए इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन को हर हिंदीप्रेमी जानता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि गांधी जी ने 1917 में भरूच में आयोजित गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में पहली सार्वजनिक तौर पर हिंदी की ताकत को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाओं में केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। हिंदी के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर भी मराठी भाषी ही थे। सतारा में जन्मे कालेलकर ने 1938 में कहा था, 'राष्ट्रभाषा प्रचार हमारा राष्ट्रीय कर्म है।' रचनात्मक आंदोलनकारी और गांधी जी के शिष्य विनोबा भी ताजिंदगी हिंदी के संघर्षरत रहे। उन्होंने हर भारतीय भाषा को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए अनूठा सुझाव दिया था। उन्होंने हर भाषा से नागरी लिपि अपनाने का सुझाव दिया था।

सिर्फ राजनीति ही नहीं, पत्रकारिता जगत की मराठीभाषी हस्तियों ने भी हिंदी को स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका निभाई है और साहस दिखाया है। हिंदी पत्रकारिता आज जिस मुकाम पर है, उसमें बड़ा योगदान मराठीभाषी पत्रकारों और लेखकों का भी है। माधव राव सप्रे, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, रामकृष्ण खाडिलकर, लक्ष्मण नारायण गर्दे जैसे पत्रकारों ने हिंदी को नई शैली में गढ़ा, उसके शब्द गढ़े, और उसे ऊंचाई दी। हिंदी इन मराठीभाषी महात्मनों की शुक्रगुजार है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से निकले धर्मयुग ने दशकों तक हिंदीभाषी पाठकों के दिलों पर राज किया। ऐसे महाराष्ट्र की धरती पर अगर हिंदी बोलने वालों का अपमान होना दुखद ही कहा जाएगा।

हिंदी को लेकर महाराष्ट्र की धरती पर अतीत में ऐसी सोच नहीं रही है। हिंदी विरोध की ग्रंथि तमिलनाडु में आजादी के पहले से ही रही है, जिसका संक्रमण कर्नाटक तक पहुंचा है। कर्नाटक रक्षण वेदिके ने 2017 में हिंदी बेड़ा अभियान यानी हिंदी विरोधी अभियान चलाया। साल 2019 में हिंदी दिवस न मनाने के लिए भी राज्य में अभियान चला। शुरू में इन विरोध प्रदर्शनों को बड़ा समर्थन नहीं मिला। राजनीति और मीडिया के हलकों में इसकी सुरसुरी दिखी। ऐसे आंदोलनों का असर बाद में पता चलता है। जब विरोध की वैचारिकी के असर में जमीनी स्तर की सोच बदलने लगती है। एक राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक से जबरदस्ती हिंदी बोलने के लिए हुज्जत करने का दृश्य हो या फिर किसी ऑटोवाले का किसी हिंदीभाषी लड़की को थप्पड़ मारना, कर्नाटक में हिंदी विरोधी आंदोलन की जमीनी परिणति ही कहा जाएगा। निजाम का शासन कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में रहा। दिल्ली सल्तनत के बादशाह मोहम्मद तुगलक ने 1327 ईस्वी में दिल्ली से महाराष्ट्र के दौलताबाद में अपनी राजधानी लेकर गया था।

वर्ग पहेली 5789

1	2	3	■	■	4	5	6
7			■	8	■	9	
	■	■	10		11	■	■
12	13	14				15	16
■	17			■	■	18	
19		■	20		21	■	
■	22	23		■	24		
■	■	25				■	■

संकेत: बाएं से दाएं

1. यह एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहलाता है (3)
4. यह देश 1814 में ब्रिटेन के अधीन हो गया था और 26 मई 1966 को राष्ट्रमंडल के भीतर स्वाधीन बना जिसकी राजधानी जार्जटाउन है (3)
7. हस्तलिखित, उपरोपित, पैबंदी (3)
9. एक बार सांस लेने का समय, बल, कश, फूंक (2)
10. किसी वी.आई.पी. के आने पर की जाने वाली तोपों का फैर (3)
12. इस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी भी कहा जाता था (8)
17. न्यौछावर करना, उत्सर्ग करना (3)
18. अंधकार, तमोगुण, विजय वासना रूपी अज्ञान (2)
19. जल, आब, नीर, पानी (2)
20. थलीय धरातल, पृथ्वी (3)
22. अनलंकृत, दर्पहीन, सरल, सामान्य (3)
24. कुएं के आसपास बना हुआ चबूतरा (4)
25. मनुहार, मनाने का काम, मन्नत (4)

ऊपर से नीचे

1. रसोईघर को यह भी कहा जाता है (4)
2. दूरी नापने की एक प्राचीन इकाई (2)
3. सुमात्रा द्वीप में होने वाली एक प्रकार की घास (2)
5. अविस्मरण, स्मृति, वियोग, दुख (2)
6. संज्ञा, इस्म, उपाधि, संज्ञिका (2)
8. मिलन, समझौता, समागमन, इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने सर्प की भूमिका निबाही थी (3)
10. श्रृंगार करना, तैयार होना, बनना-ठनना (6)
11. प्रेमी, पुरूष मित्र को यह भी कहा जाता है (2)
13. उत्तराधिकारी, अनाथ, स्वामीहीन (4)
14. राल, लुआबा, लासा (2)
15. निशा, विभावरी, रात्रि, रजनी (2)
16. यमराज की भेजे जाने वाले संदेशवाहक (4)
21. पंडवानी शैली की प्रसिद्ध लोकगायिका (3)
23. समाकार, समकोटीय, अनेतर, सदृश्य (2)

वर्ग पहेली 5788 का हल

ब	ह	री	न	■	म	हु	आ
या	र	■	म	दी	ना	■	स
र	फ	बु	क	■	व	■	पा
■	■	त	ह	स	न	ह	स
सु	ख	■	ला	वा	■	स्ती	■
न	ल	■	ल	लि	ता	■	फौ
य	■	आ	■	या	र	बा	ज
ना	म	ज	द	■	क	र	■

खतरे में मनसे का चुनावी अस्तित्व, मुंबई तक सिमटी शिवसेना-यूबीटी कैसे जादू दिखाएगा ठाकरे बंधुओं का गठबंधन?

(प्रेम शुक्ल)

महाराष्ट्र में इन दिनों ठाकरे बंधुओं की एकता का समाचार सुर्खियों में है। दोनों भाइयों के एक मंच पर आने के बाद से ही कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि राज और उद्धव इस एकता का लाभ उठाने में सफल होंगे। क्या यह संभव है? क्या महानगर पालिका चुनावों से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों में शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपसी गठबंधन से कोई चुनावी चमत्कार कर सकते हैं?

गठबंधन का फॉर्मूयुला: गठबंधन से पहले 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 2 और भाजपा के 14 विधायक थे। बालासाहेब ठाकरे और प्रमोद महाजन ने जो गठबंधन बनाया, उसमें शिवसेना को 171 और भाजपा को 117 विधानसभा सीटें मिलीं। चुनाव में शिवसेना के 51 और भाजपा के 42 विधायक निर्वाचित हुए। बीजेपी14 से 42 तक पहुंची तो शिवसेना 2 से 51 पर। साफ है कि गठबंधन का ज्यादा लाभ किसे मिला। 1995 में जब पहली बार शिवसेना-भाजपा सत्ता में आई, तब शिवसेना को मिले थे 74 और भाजपा को 64 विधायक। उस चुनाव में भी 171-117 वाले फॉर्मूयुले पर ही गठबंधन हुआ था।

शिवसेना की नैया: शिवसेना के हिंदुत्व के उफान, बालासाहेब ठाकरे की लोकप्रियता के उत्कर्ष और भाजपा के साथ गठबंधन के बाद अब तक शिवसेना को मिली सबसे बड़ी चुनावी सफलता का आंकड़ा 74 का है । शिवसेना को उसके बाद 1999 में 68 और 2004 में 62 सीटों पर सफलता मिली। 2004 में पहले जब नारायण राणे, फिर राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत की, तो 2009 के चुनावों में पार्टी 45 सीटों पर सिमट गई। तब राज ठाकरे के मनसे के 12 विधायक चुने गए थे। शिवसेना-मनसे और नारायण राणे - सब मिलकर 62 सीटों पर ही थे। 2007 और 2012 के मनपा चुनाव में भी शिवसेना की नैया भाजपा के साथ हुए गठबंधन से ही पार लगी थी।

फिर आई मोदी लहर: 2014 का विधानसभा चुनाव मोदी लहर का चुनाव था। पहली बार शिवसेना के 18 सांसद लोकसभा पहुंचे थे। तब बीजेपी ने अपनी बढ़ी शक्ति के दम पर 117 सीटों को 126 तक करने की जायज मांग रखी। शिवसेना को 152 सीटें दी जा रही थीं, जिनमें उसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अन्य सहयोगियों को एडजस्ट करना था। शिवसेना अड़ गई और ढाई दशक बाद गठबंधन टूट गया। विधानसभा चुनाव में भाजपा को 123 सीटों पर सफलता मिली, जबकि शिवसेना 63 सीटों पर ही सिमटी रही।

मराठी मानुष का भरोसा: उद्धव और राज ठाकरे शिवसेना में 1995 के बाद पदासीन हुए। उनकी जिम्मेदारी में शिवसेना का पहला चुनाव 1999 का माना जाएगा। एकीकृत शिवसेना को 1999 से 2019 तक, कुल 294 विधानसभा सीटों पर जीत मिली।

आज का राशिफल

मेष

आज उन्नति के संयोग बन रहे हैं। जीवनसाथी से आर्थिक मामलों में सक्रिय सहयोग मिलेगा। परिवार में कोई फिक्स्ड डिपॉजिट या इंश्योरेंस पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है। अनपेक्षित खर्चे, विशेषकर बच्चों की शिक्षा, ऑनलाइन कोर्स या होम रिपेयर पर हो सकते हैं। बिजनस में कोई पुराना सहयोगी दोबारा संपर्क कर सकता है।

वृष

आज कार्यक्षेत्र में उन्नति के मजबूत योग हैं। किसी सरकारी अफसर, राजनीतिक जान-पहचान या पुराने निवेशक से मिलने वाला सहयोग आपके कारोबार का विस्तार कर सकता है। फंडिंग या व्यापारिक ऋण के लिए अप्लाई करना फलदायी रहेगा। शेयर मार्केट में सावधानी से किया गया छोटा निवेश लाभकारी रहेगा।

मिथुन

आज सावधानी के साथ काम करने की सलाह है। महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डॉक्युमेंट्स और मोबाइल या ई-वॉलेट की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संतान की सफलता भविष्य में निवेश की दिशा तय कर सकती है। मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, ब्लॉगिंग और कोचिंग क्लास जैसे क्षेत्रों में कार्यरत जातकों के लिए नई डील मिल सकती है।

कर्क

आज संपत्ति, वाहन, लोन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। यदि आप रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री या कैटरिंग से जुड़े हैं, तो किसी क्लाइंट से बड़ी डील फाइनल हो सकती है। चंद्रमा की शुभ स्थिति से माता-पिता की सहायता से कोई पारिवारिक निवेश योजना साकार हो सकती है।

सिंह

आज भाग्य साथ दे रहा है। वाणी की मधुरता और नेटवर्किंग स्किल्स से बड़े कॉर्पोरेट या सरकारी क्लाइंट्स से संपर्क बन सकता है। पत्रकारिता, शिक्षा, विज्ञापन और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता या इंटरव्यू का बुलावा मिल सकता है। शेयर बाजार से जुड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लें।

कन्या

आज दिन तरक्की लेकर आएगा। नौकरी और व्यवसाय से जुड़ी बड़ी सफलता मिल सकती है। जिन लोगों ने सरकारी योजनाओं में निवेश किया है, उन्हें रिटर्न मिलने का योग बन रहा है। टैक्स, ऑडिट, कानूनी फाइलिंग आदि में लंबित कार्य पूरे होंगे।

तुला

आज धन प्राप्ति के मामले में दिन अनुकूल है। पुराना निवेश जैसे पीपीएफ, एलआईसी या पोस्ट ऑफिस स्कीम से लाभ हो सकता है। व्यापार में कोई बड़ी पेमेंट क्लियर हो सकती है जिससे राहत मिलेगी। यदि आप आयात-निर्यात, स्टेशनरी, हेल्थकेयर या ऑनलाइन शॉपिंग बिजनस में हैं तो नए ग्राहक जुड़ेंगे।

वृश्चिक

आज उन्नति के योग बने हैं। अनचाहे खर्चों की संभावना है। विशेषकर हेल्थ और कानूनी मामलों में। ग्रहों की दशा थोड़ी मानसिक अस्थिरता और जल्दबाजी में गलत निर्णय की प्रवृत्ति ला सकता है। इस कारण निवेश से पहले सलाह अवश्य लें। यदि आप रिसर्च, आयुर्वेद, मेडिकल या साइंटिफिक क्षेत्र में कार्यरत हैं तो कोई नई उपलब्धि मिलेगी।

धनु

आज दिन अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर, ग्रांट्स या स्कॉलरशिप के जरिए धन प्राप्ति के योग हैं। यदि आप कोई जॉब स्विच की सोच रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त अवसर आ सकता है। करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं, विशेषकर वो लोग जो विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं। नेटवर्किंग, पब्लिक स्पीकिंग या कॉर्पोरेट प्रजेंटेशन से भी आय का स्रोत बन सकता है।

मकर

आज भाग्य साथ दे रहा है। रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक संकेत मिलेंगे। बैंक लोन स्वीकृति, प्रॉपर्टी फाइनल या बकाया बिल की प्राप्ति जैसे कार्यों में प्रगति होगी। किसी स्टार्टअप या फैमिली बिजनस में पूंजी निवेश से आर्थिक वृद्धि संभव है। यदि आप खुदरा व्यापार में हैं तो कस्टमर बेस बढ़ेगा। फाइनेंशियल डॉक्युमेंट्स और करारों में पूर्ण स्पष्टता रखें।

कुंभ

आज समझदारी से काम लेने की सलाह है। आर्थिक निर्णय लेते समय भ्रम की स्थिति से बचें। शनि की स्थिति अनावश्यक भ्रम, संशय या देरी करा सकती है। नौकरी या बिजनस में बदलाव की सोच रहे हैं तो रिसर्च और तैयारी में दिन बिताएं। हेल्थ पर खर्च संभव है, इसलिए इंश्योरेंस या हेल्थ प्लानिंग पर ध्यान दें। क्रिप्टो, कमोडिटी या डे ट्रेडिंग से पूरी तरह बचें।

मीन

आज निवेश से लाभ के विशेष योग हैं। विशेषकर पारंपरिक योजनाएं जैसे म्युचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड या पीपीएफ धन वृद्धि करेंगी। धार्मिक या परोपकारी कार्यों में खर्च बढ़ेगा, लेकिन उससे आपको सामाजिक मान भी मिलेगा। पुराने संपर्कों से दोबारा व्यापार या क्लाइंट के रूप में जुड़ने के संकेत हैं।

वित्त मंत्रालय के अधीन आ सकता है क्लेम पोर्टल

बेहिसाब मेडिकल बिल पर नकेल कसने जा रही सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में बढ़ते मेडिकल बिल और बेहिसाब खर्चों पर केंद्र सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। एक सरकारी सूत्र के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार मौजूदा मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम पोर्टल्स को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने की योजना बना रही है। सूत्रों ने कहा कि इसका मकसद तमाम स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं यानी अस्पतालों द्वारा मरीजों और बीमाकृत व्यक्तियों से बेहिसाब मेडिकल बिल की उगाही पर लगाम लगाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना इस बात की भी है कि भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (आईआरडीएआई) स्वास्थ्य प्रदाताओं की निगरानी करे, ताकि मरीजों की जेब पर अनावश्यक बोझ न पड़े।

पेशेवर सेवा फर्म एओन की ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड रेट्स रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत में स्वास्थ्य सेवा लागत में 13प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है, जो वैश्विक औसत 10प्रतिशत से ज्यादा है। एक साल पहले यह 12 फीसदी था।

सरकार और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई द्वारा किए गए एक विश्लेषण में पाया गया है कि अस्पताल मरीजों के इलाज की लागत बढ़ा रहे हैं और उच्च कवर वाले मरीजों से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। सूत्र ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए बताया कि इस वजह से बीमा कंपनियाँ ज़्यादा स्वास्थ्य प्रीमियम वसूल रही हैं। भारत के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालयों ने रॉयटर्स के टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया है।

हेल्थ क्लेम एक्सचेंज करेगा सख्त निगरानी

सूत्र ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ क्लेम एक्सचेंज (जो बीमा कंपनियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और मरीजों के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करता है) की सख्त निगरानी से बीमा कंपनियों की इलाज दरें निर्धारित करने की सामूहिक सौदेबाजी शक्ति में सुधार हो सकेगा। फिलहाल, इस एक्सचेंज की देखरेख स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा की जाती है। प्राधिकरण की वेबसाइट के अनुसार, इसे बीमा नियामक के साथ परामर्श से विकसित किया गया है।

बीमा कंपनियों की प्रीमियम आय घटी

बता दें कि आईआरडीएआई हेल्थ एक्सचेंज को रेग्युलेट नहीं करता है, लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म पर बीमा कंपनियों को जरूर रेग्युलेट करता है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम आय में वार्षिक वृद्धि एक साल पहले के 20प्रतिशत से घटकर 2024-25 में सिर्फ 9प्रतिशत रह गई है, क्योंकि महंगे प्रीमियम का बोझ कई लोगों की क्षमता से बाहर गए हैं। इस वजह से हेल्थ पॉलिसी नवीनीकरण कम हो रहे हैं।

कन्हैयालाल की हत्या पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर हाई कोर्ट ने लगा दी रोक

जयपुर, एजेंसी। उदयपुर फाइल्स के निर्माताओं को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी। रिलीज से एक दिन पहले ही हाई कोर्ट ने फिलहाल के लिए इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है।

रोक लगाते हुए मुख्य न्यायधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र का रुख करने के लिए दो दिन का समय दिया है।

क्या बोले याचिकाकर्ता

बता दें कि उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड की घटना पर आधारित यह फिल्म बनाई गई है। इस मामले में आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि इस फिल्म की रिलीज के बाद उनके केस की निष्पक्ष सुनवाई की संभावना खतरे में पड़ सकती है। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने केंद्र से मिलने वाले उपायों का इस्तेमाल नहीं किया है। जस्टिस डीके उपाध्याय और अनीश दयाल की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को लेकर कहा कि हमने याचिकाकर्ताओं को पुनरीक्षण उपाय लागू करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, इसलिए जब तक केंद्र सरकार द्वारा इस मामले पर दिए आवेदन पर निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगी रहेगी। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की जून 2022 में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस को गिरफ्तार किया गया था।

कन्हैयालाल की हत्या के बाद हमलावरों ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया था कि यह हत्या दर्जी की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर की गई है। हमलावरों ने कहा था कि कन्हैयालाल ने नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी का समर्थन करते हुए एक पोस्ट किया था, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की थी। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा के अलावा यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला जयपुर की स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट ने इस केस पर आधारित फिल्म पर रोक लगा दी है।

संक्षिप्त समाचार

फरीदाबाद में अनंगपुर के बाद लकड़पुर में भी बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी, 313 अवैध निर्माणों को नोटिस

फरीदाबाद, एजेंसी। फरीदाबाद के अनंगपुर के बाद अब लकड़पुर में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई खतरा मंडराने लगा है। वन विभाग लकड़पुर का रिकॉर्ड खंगाल रहा है। विभाग ने 313 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया है, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। फिलहाल एक सप्ताह से वन विभाग की कार्रवाई रुकी हुई और उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद ही आगे कार्रवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले महीने करीब 15 दिनों तक अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके तहत वन विभाग 240 अवैध निर्माणों को गिराकर वन विभाग की करीब 270 एकड़ जमीन को खाली कराया है। वन विभाग ने इस कार्रवाई की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी है और अब उच्च अधिकारियों के अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अनखीर, मेवला महाराजपुर, लकड़पुर और अनंगपुर में करीब 800 एकड़ जमीन पर 6793 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। इनमें से अनंगपुर में 5948, लकड़पुर में 313, मेवला महाराजपुर में 193 और अनखीर में 339 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया है। वन विभाग जल्द ही अपनी शेष 530 एकड़ जमीन भी जल्द ही कब्जा मुक्त कराएगा। अनंगपुर संघर्ष समिति द्वारा 13 जुलाई को सूरजकुंड गोल चक्कर पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें एक लाख लोगों की संभावना है। महापंचायत में शामिल होने के लिए लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। अनंगपुर गांव के अलावा जगहों से आने वाले लोग एकत्रित होकर पिछले दिनों की गई कार्रवाई के दौरान गिराए निर्माणों के मालिकों को मुआवजा दिलवाने की मांग करेंगे। इसके अलावा वर्ष 2031 के मास्टर प्लान में अनंगपुर को वन क्षेत्र से बाहर किया जाए। विपिन सिंह, जिला वन अधिकारी, हमने वन विभाग की करीब 270 एकड़ जमीन को अवैध निर्माणों को मुक्त कराया है। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। लकड़पुर में 313 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। शेष बचे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई उच्च अधिकारियों के आदेश पर होगी।

अब असम में भाषा को लेकर विवाद, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा बोले- ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी

दिसपुर, एजेंसी। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद के बीच असम में भी भाषा को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। एक अल्पसंख्यक छात्र नेता द्वारा असम में जनगणना के दौरान मुस्लिमों से असमिया की जगह पर बंगाली भाषा को अपनी मातृ भाषा लिखने की अपील की गई। छात्र नेता की इस अपील के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चेतावनी दी है। सीएम ने असमिया भाषा को असम की स्थायी राज भाषा बताते हुए कहा कि किसी को भी भाषा का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के औजार के रूप में नहीं करना चाहिए। भाषा विवाद के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, असमिया असम की स्थायी आधिकारिक भाषा है। इसकी संवैधानिक वैधता है। भाषा को ब्लैकमेल करने के हथियार के रूप में नहीं लिया जा सकता। अगर वे असमिया को अपनी मातृभाषा के रूप में सूचीबद्ध नहीं भी करते हैं, तो भी इससे तथ्य नहीं बदलेंगे। हालांकि अगर समुदाय असमिया को अपनी मातृभाषा के रूप में सूचीबद्ध नहीं करता है तो इससे केवल यह पता चलेगा कि राज्य में कितने अवैध विदेशी हैं। आपको बता दें यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब ऑल बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल माइनॉरिटी के छात्र यूनियन के नेता मैनुद्दीन अली ने आगामी जनगणना में बंगाली मुस्लिमों को मातृभाषा के रूप में असमिया न लिखने की अपील की थी। उसने कहा कि ऐसा करने पर असम में असमिया बहुसंख्यकों की भाषा नहीं रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र नेता के इस विवादित बयान के बाद ऑल बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल माइनॉरिटी ने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही छात्र नेता ने अपने इस बयान के लिए माफी भी मांग ली है।

ओडिशा में बांग्लादेशी समझ पुलिस ने कई भारतीयों को पकड़ा, दो दिन बाद कागज देखकर छोड़ा

भुवनेश्वर, एजेंसी। ओडिसा पुलिस ने पिछले दिनों 444 प्रवासी मजदूरों को झारसुगड़ा क्षेत्र से संदिग्ध मानकर गिरफ्तार किया था। अब कुछ दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने के बाद इनमें से कई श्रमिकों को छोड़ दिया है। रिहा किए गए इन बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों ने ओडिसा पुलिस के ऊपर उन्हें परेशान करने और पिछले तीन दिनों से हिरासत केंद्रों में रखने का आरोप लगाया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत में लिए गए इन प्रवासी मजदूरों से पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट जैसे कागजातों की मांग की। चूंकि ज्यादातर मजदूर पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों के आते हैं, ऐसे में उनके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट मौजूद नहीं थे। दस्तावेज न होने की स्थिति में उनकी रिहाई में और भी ज्यादा देरी हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट की अनुपलब्धता के बाद अन्य दस्तावेजों की मांग की लेकिन उसके सत्यापित होने में काफी समय लग गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए एक प्रवासी मजदूर के रिश्तेदार ने कहा, मेरे बहनोई 37 साल के हैं। हमारे इलाके में उनके जन्म के समय कोई भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं करता था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमें अपनी भारतीयता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कहा जाएगा। हिरासत में लिए गए मजदूरों के रिश्तेदारों ने बताया कि अपने लोगों की रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपने गृह जिलों मुर्शिदाबाद और हुगली से अपनी जमीनों के दस्तावेजों को मंगवाया और अपने कई दूसरे रिश्तेदारों के आधार कार्डों को भी जमा किया। इन कागजातों को जमा करने के बाद पुलिस ने एक लंबी प्रक्रिया के तहत इनका सत्यापान किया और कई लोगों को रिहा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहाई के बाद मजदूरों को उनकी नौकरियों पर लौटने की इजाजत दी गई है।

जहां 10,000 आबादी, वहां जाकर पीएम ले रहे सम्मान इतना तो जेसीबी देखने आ जाते हैं: भगवंत मान

चंडीगढ़/नई दिल्ली, एजेंसी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों और इस दौरान उन्हें मिले कई देशों के सर्वोच्च सम्मान पर तंज कसा है। चंडीगढ़ में सीएम मान ने कहा, पीएम घाना गए हैं, कहां गए हैं पता नहीं कौन-कौन से देश मैग्नीशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहां-कहां जा रहे हैं।

जहां 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, वहां रह नहीं रहे और जिस देश में जा रहे हैं उसकी आबादी कितनी है महज 10 हजार है और सबसे बड़ा अवॉर्ड वहां का मिल गया। सीएम मान ने कहा कि 10 हजार लोग तो जेसीबी देखने के लिए आ जाते हैं यहां। अब क्या मोदी वाले सवाल भी मुझ से ही पूछोगे कि उन्होंने ग्यारह साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैं तो रोज तीन करता हूं।

विदेश मंत्रालय की तल्ख टिप्पणी

इधर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पंजाब सीएम के बयान पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये टिप्पणियां गैर-ज़िम्मेदाराना और खेदजनक हैं और सरकार में शीर्ष पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देतीं। उन्होंने कहा, हमने एक उच्च सरकारी प्राधिकारी द्वारा ग्लोबल साउथ के मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में की गई कुछ टिप्पणियाँ देखी हैं। ये टिप्पणियाँ गैर-ज़िम्मेदाराना और खेदजनक हैं और सरकारी प्राधिकारी को शोभा नहीं देतीं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कमज़ोर करती हैं।

ट्रंप के कहने पर सिंधु जल संधि बहाल मत कर देना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि एसवाईएल के मुद्दे पर कल ही बैठक हुई थी। मैंने वहां बोला है कि सिंधु जल संधि आपने रद्द कर दी, कृपया इसको ट्रंप के कहे या किसी अन्य दबाव की वजह से फिर से बहाल मत करना। झेलम का पानी हमारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि वो दूर है। चिनाब, रावी और कश्मीर की उझ दरिया का सारा पानी पंजाब आ जाए। पौंग डैम या फिर रणजीत सागर या भाखड़ा में आ जाए। वह 23 एमएएफ पानी आ सकता है जबकि एसवाईएल का झगड़ा एक या दो एमएएफ के लिए ही है। अगर 23 एमएएफ आ गया तो मैं कहां संभालूंगा। नहरें बनानी पड़ेंगी। पंजाब को भी पानी मिलेगा, आगे अरब सागर में भी जा सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर को बताया था भाजपा की वन नेशन वन हसबैंड स्कीम

मई में पाकिस्तान के खिलाफ की गई भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाजपा घर-घर जाकर सिंदूर बांटेगी, उन्होंने कहा था कि क्या आप मोदी के नाम का सिंदूर लगाएंगे क्या यह एक राष्ट्र, एक पति योजना है उन्होंने भाजपा पर इसका राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया था। बता दें कि 7 मई को भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में कई आतंकी ढांचे को निशाना बनाया था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े सैकड़ों आतंकवादी मारे गए थे।

संजय गांधी ने जबरन कराई नसबंदियां दिल्ली में हजारों हुए बेघर: शशि थरूर

नईदिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साल 1975 में लगे आपातकाल पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में एक लेख में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र हल्के में ली जाने वाली चीज नहीं है। खास बात है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश गए थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ को लेकर भी पार्टी नेताओं के निशाने पर आ गए थे।

मलयालम दैनिक 'दीपिका' में गुरुवार को आपातकाल पर प्रकाशित एक लेख में कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले दौर को याद किया और कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास अक्सर क्रूरतापूर्ण कृत्यों में बदल जाते हैं जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता था। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने लिखा, इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया जो इसका एक संगीन उदाहरण बन गया। पिछड़े ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और बल का इस्तेमाल किया गया। नई दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बेरहमी से ध्वस्त कर उनका सफाया कर दिया गया। हजारों लोग बेघर हो गए। उनके कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए, यह एक अनमोल विरासत है जिसे निरंतर पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। थरूर ने कहा, यह सभी को हमेशा याद दिलाता रहे।

थरूर के अनुसार, आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। उन्होंने कहा, हम ज्यादा आत्मविश्वासी, यादा विकसित और कई मायनों में यादा मजबूत लोकतंत्र हैं। फिर भी, आपातकाल के सबक चिंताजनक रूप से प्रासंगिक बने हुए हैं। थरूर ने चेतावनी दी कि सत्ता को केंद्रीकृत करने, असहमति को दबाने और संवैधानिक रक्षात्मक उपायों को दरकिनार करने की प्रवृत्ति विभिन्न रूपों में फिर से उभर सकती है। उन्होंने कहा, अक्सर ऐसी प्रवृत्तियों को राष्ट्रीय हित या स्थिरता के नाम पर उचित ठहराया जा सकता है। इस लिहाज से आपातकाल एक कड़ी चेतावनी है। लोकतंत्र के प्रहरियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए।

पंजाब के मंत्री ने लगाए बड़े आरोप, कहा- लॉरेंस बिश्नोई को भाजपा बचा रही है

जालंधर, एजेंसी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उन राज्यों को हिंसा के जरिए अस्थिर करने की कोशिशों के तहत कुख्यात अपराधियों को संरक्षण दे रही है जहां उसका शासन नहीं है। चीमा ने अबोहर के व्यवसायी संजय वर्मा की हाल ही में हुई हत्या का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, जो गुजरात सरकार के 'संरक्षण' में वहां की जेल में बंद है।

चीमा ने सवाल किया, उसे (बिश्नोई को) सुरक्षा क्यों दी गई है और उसे जेल में क्यों रखा गया है पंजाब के वित्तमंत्री ने सवाल किया, लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात कौन ले गया और उसे वहां क्यों सुरक्षित रखा जा रहा है ऐसा लगता है कि भाजपा उसे इसलिए बचा रही है ताकि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में अशांति पैदा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को निशाना बनाने और समाज में भय फैलाने के लिए कुख्यात अपराधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीमा ने आरोप लगाया, जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में नहीं है, वहां वे शांति भंग करने के लिए अपराधियों और गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह देश के संघीय ढांचे और कानून-व्यवस्था के खिलाफ एक खतरनाक साजिश है। 'न्यू वेयर वेल जेंट्स टेलर' शोरूम के सह-मालिक वर्मा की सात जुलाई को अबोहर के व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र भगत सिंह चौक के पास दिनदहाड़े तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

छत्तीसगढ़ में 14 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र, कई मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस

966 सवाल तैयार

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में जमकर हंगामा होने के आसार हैं। यह सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल पांच बैठकें होंगी। समय कम होने की वजह से भाजपा सरकार को घेरने के लिए विपक्षी कांग्रेस हर दिन स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसकी अंतिम रणनीति कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनेगी। विधानसभा सदन में विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों के भी तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं।

छत्तीसगढ़ मानसून सत्र के लिए विधायकों ने 996 सवाल लगाए हैं। राज्य सरकार को करीब डेढ़ साल हो गए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भाजपा सरकार में हुई गड़बड़ियों के सवाल को प्रमुखता से उठाया जाएगा। मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। किसानों को खाद-बीज की समस्या, कानून व्यवस्था, शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण, पेड़ की कटाई, अवैध रेत उत्खनन और परिवहन, शराब की अवैध बिक्री, सीजीएमएससी दवा खरीदी आदि मुद्दों पर सवाल लगे हैं। रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कारिडोर यानी भारतमाला परियोजना पर भी सदन गरमा सकता है।

सरकार पूरी तरह से तैयार : साय

मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार कई विधेयक पेश भी कर सकती है, जिसमें राजस्व, आवास एवं पर्यावरण विभाग के विधेयक आने की संभावना है। वहीं राज्य सरकार द्वारा अन्य विषयों पर भी विधेयक लाया जा सकता है। सत्र के दौरान राज्य सरकार अनुपूरक बजट भी ला सकती है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। प्रदेश में भाजपा सरकार बेहतरी से काम कर रही है।

विपक्षी कांग्रेस के आक्रामक रहेंगे तेवर : मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मानसून सत्र के दौरान आक्रामक तेवर दिखाएगा। भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार के कामकाज को लेकर कई सवालों के अलावा चर्चा के दौरान विभागों में चल रही गड़बड़ियों पर सवाल उठाएगा। कांग्रेस के शीर्ष संगठन द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद सदन में सरकार को घेरने विपक्ष तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इसकी रणनीति तय होगी। दो दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस की बड़ी बैठक ली थी। इसमें सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर घेरने की नसीहत भी दी गई है।

टेस्ट के बाद ओडीआई कप्तान बनेंगे शुभमन गिल!

नई दिल्ली, एजेंसी। रोहित शर्मा की टेस्ट रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया. गिल, जो अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर भारतीय ओडीआई टीम का कप्तान बदले जाने का टॉपिक ट्रेंड कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि अगली वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा नहीं बल्कि शुभमन गिल कर सकते हैं. 2027 वनडे वर्ल्ड कप में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन रोहित कब तक अपनी कप्तानी को सुरक्षित रख पाएंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है.

वहीं एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है भारत जब भी अपनी अगली एकदिवसीय श्रृंखला खेलेगा, उसमें रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल कप्तानी करेंगे. मौजूदा शेड्यूल पर नजर डालें तो टीम इंडिया को अगली ओडीआई सीरीज अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है.

शुभमन गिल के अभी तक ओडीआई करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 55 मैचों में 59.04 के बेहद शानदार औसत से 2,775 रन बनाए हैं. एकदिवसीय क्रिकेट में उनके नाम 8 शतक और 15 हाफ-सेंचुरी भी हैं.

कब होगी टीम इंडिया की अगली ओडीआई सीरीज: भारतीय टीम की अगली ओडीआई सीरीज अगस्त महीने में बांग्लादेश के साथ होने वाली थी, लेकिन इस दौरे को रद्द कर दिया गया है. अगर बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज नहीं हो पाती है तो टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी.

वैभव सूर्यवंशी-आयुष होंगे ओपनर

इंग्लैंड के खिलाफ पहले यूथ टेस्ट के लिए इंडिया की प्लेइंग इलेवन

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम और इंग्लैंड अंडर 19 क्रिकेट टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी और इस सीरीज का पहला मैच 12 जुलाई से शुरू होगा। इस टेस्ट सीरीज में एक मैच 4 दिनों का होगा और दोनों टीमें पहले मुकाबले में केंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड, बेकेनहम में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे। इस मैच की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3.30 बजे से होगी।

इंडिया अंडर 19 टीम ने इस टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड की टीम को 5 मैचों की वनडे सीरीज में 3-2 से हराया था। हालांकि इस वनडे सीरीज के आखिरी मैच में इंडिया को हार मिली थी। अब बारी रेड बॉल क्रिकेट की है जहां दोनों टीमों के धैर्य की परीक्षा होगी और बेहतर खेलने वाली टीम जीत हासिल करेगी। वैसे वनडे सीरीज में जीत के बाद अब इंडिया के पास इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में भी रौंदने का बेहतर मौका है।

वैभव-आयुष कर सकते हैं ओपन

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी वही टीम हिस्सा लेगी जिस टीम ने वनडे सीरीज में हिस्सा लिया था, लेकिन यहां चुनौती कुछ अलग होने वाली है, लेकिन इंडिया ने जिस तरह का दम दिखाया उससे उम्मीद है कि टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। पहले यूथ टेस्ट के लिए अगर इंडिया की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो इसमें एक बार फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष महात्रे के हाथों में हो सकती है।

वैभव के लिए रेड बॉल क्रिकेट में खुद को साबित करने का मौका

वैभव ने पिछले साल भी यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ दो मैच खेले थे और उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा वनडे में उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें रेड बॉल में भी ओपनिंग का मौका दिया जा सकता है। वैभव के लिए भी रेड बॉल क्रिकेट में खुद को साबित करने का अच्छा मौका होगा।

इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में अभिज्ञान कुंडू को बाहर बिठाया गया था, लेकिन पहले टेस्ट मैच के लिए उनकी प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है। भारतीय बैटिंग क्रम में इसके अलावा विहान मलहोत्रा, राहुल कुमार, कनिष्क चौहान होंगे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अंबरीश, दीपेश देवेंद्रन, अनमोलजीत सिंह, युद्धजीत गुहा और नमन पुष्पक के हाथों में होगी।

पहले यूथ टेस्ट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की प्लेइंग इलेवन

आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, राहुल कुमार, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, दीपेश देवेंद्रन, अनमोलजीत सिंह, युधाजीत गुहा, नमन पुष्पक।

अगर टेनिस खेलते सूर्यकुमार तो...

धोनी को चुनते अपना डबल्स पार्टनर

लंदन, एजेंसी। सूर्यकुमार पहली बार विंबलडन देखने के लिए पहुंचे थे। वहां मौजूदगी से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं। विंबलडन ने भी उनकी एक फोटो शेयर की और लिखा, एसडब्ल्यू19 में रौनक लेकर आए सूर्यकुमार यादव!

आपको यहां देखकर खुशी हुई। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन क्रिकेटरों में शुमार हैं, जिन्होंने सेंटर कोर्ट का दौरा किया और विंबलडन मैच देखा। वह हाल ही में पत्नी देविशा शेट्टी के साथ मैच देखने पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान खुलासा किया कि वह अपने डबल्स जोड़ीदार के तौर पर भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को देखना पसंद करेंगे। सूर्यकुमार पहली बार विंबलडन देखने के लिए पहुंचे थे। वहां मौजूदगी से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं। विंबलडन ने भी उनकी एक फोटो शेयर की और लिखा, एसडब्ल्यू19 में रौनक लेकर आए सूर्यकुमार यादव! आपको यहां देखकर खुशी हुई। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह भी पत्नी संजना के साथ मैच देखने सेंटर कोर्ट पहुंचे थे। टेनिस को लेकर अपने लगाव के बारे में सूर्यकुमार ने बताया, मैं टीवी पर टेनिस बहुत देखता हूं। सेंटर कोर्ट के माहौल के बारे में हमेशा सुना करता था, खास तौर पर तब जब खिलाड़ी वहां प्रवेश करते हैं। अब इसे सामने से महसूस किया, यह बहुत ही खास अनुभव है।

जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें किसी क्रिकेटर को टेनिस डबल्स (पुरुष युगल) पार्टनर चुनना हो, तो वे किसे चुनेंगे? इस पर सूर्यकुमार ने कहा, बिलकुल एमएस धोनी को। वह तेज हैं, सहनशक्ति बहुत ज्यादा है और मानसिक रूप से बेहद मजबूत हैं। और हाल ही में जब वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं, तो मैंने उन्हें कई बार टेनिस खेलते देखा है। इसलिए मेरी पहली पसंद वही होंगे।

लॉर्ड्स टेस्ट

इंग्लैंड पहली पारी में 387 रन पर ऑलआउट, जसप्रीत बुमराह को 5 विकेट

- रूट का शतक, कार्स ने 56 रन बनाए

लंदन, एजेंसी। बुमराह ने इस सीरीज में दूसरी बार 5 विकेट हॉल हासिल किया है। उन्होंने जोफा आर्चर, क्रिस वोक्स, जो रूट बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक को आउट किया। भारत ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में 387 रन पर ऑलआउट कर दिया है। शुक्रवार को मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 251/4 के स्कोर से खेलना शुरू किया।

लंच से पहले इंग्लिश टीम ने 271 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। यहां से जैमी स्मिथ (51 रन) ने ब्रायडन कार्स (56 रन) के साथ 8वें विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी करके स्कोर 350 पार पहुंचा दिया। लॉर्ड्स मैदान पर 99 रन से पारी को आगे बढ़ाने वाले जो रूट ने 104 रन बनाए। उन्हें जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड कर दिया। बुमराह ने पारी में 5 विकेट झटके। उन्होंने इस सीरीज में दूसरी और करियर में 15वीं बार पारी में 5 विकेट झटके हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए

100 टेस्ट खेलना बड़ी उपलब्धि: मिचेल स्टार्क

किंग्स्टन, एजेंसी। रविवार को अपने ऐतिहासिक 100वें टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपने करियर के उतार-चढ़ाव और चोटों से जूझने के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने चुनौतियों को पार करते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपनी स्थायी छाप छोड़ी। स्टार्क ने इस उपलब्धि को बड़ा सम्मान करार दिया और कहा कि वह इस पर तब विचार करेंगे जब वह खेल से संन्यास लेंगे। रविवार को किंग्स्टन में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में मैदान पर उतरते ही स्टार्क यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बन जाएंगे। इससे पहले ग्लेन मैक्ग्रा यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। डे नाइट मैच में ऑस्ट्रेलिया के पास सीरीज में क्लीन स्वीप करने का भी मौका होगा। स्टार्क ने अपने 100वें टेस्ट मैच से पहले क्रिकेट.कॉम.एयू से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने अपनी शारीरिक देखभाल और दृढ़ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैंने अपने शरीर का ध्यान रखा है और चोटों के बीच खुद को फिट रखने के तरीके खोज पाया जिससे मैं टीम के लिए उल्लेखनीय योगदान दे सकूं। स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के 471 टेस्ट क्रिकेटरों में से केवल 15वें खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 100 टेस्ट मैचों की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा, मैं पहले भी एक ऐसा खिलाड़ी रहा हूं जो चोटिल हो चुका है और टीम को एक खिलाड़ी कम होने का झटका दे चुका है, और मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करना चाहता था।

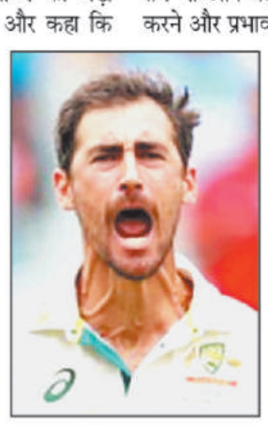

इसलिए जब चीजें ठीक नहीं चल रही हों, या दर्द हो रहा हो, या मैं किसी चीज से परेशान हो रहा हो, तब भी आगे बढ़ने और मैच खत्म करने और प्रभावशाली बने रहने के तरीके खोजना अहम होता है। यही प्रक्रिया रहती है। मुझे अपनी फिटनेस बनाए रखने में प्रशिक्षकों और फिजियोथेरेपिस्टों से भी काफी मदद मिली, और मेरे सबसे अच्छे साथियों ने भी मेरी मदद की, जिससे मैं खेलता रहा और टीम का हिस्सा बना रहा। स्टार्क अपने 100वें टेस्ट मैच में किंग्स्टन में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के करीब हैं।

99 टेस्ट मैचों में 395 विकेट ले चुके स्टार्क को 400 टेस्ट विकेट के आंकड़े तक पहुंचने के लिए केवल पांच और विकेट चाहिए। यदि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मैच में यह कारनामा कर लेते हैं, तो वह ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा के साथ टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएंगे। मैकग्रा ने अपने करियर में 124 टेस्ट में 563 विकेट लिए थे।

लारा के सम्मान में 400 से पहले घोषित कर दी थी पारी, मुल्डर ने दिग्गज बल्लेबाज की प्रतिक्रिया शेयर की

बुलावायो, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने कहा है कि ब्रायन लारा ने उनसे कहा था कि उन्हें टेस्ट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाना चाहिए था। बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मुल्डर ने लंच ब्रेक के दौरान पारी घोषित कर दी थी तब मुल्डर 367 के निजी स्कोर पर नाबाद थे।

इस फैसले के बाद मुल्डर 2004 में, एंटीगा में इंग्लैंड के खिलाफ लारा द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड नाबाद 400 रन से 33 रन दूर रह गए थे। मुल्डर ने पारी घोषित करने के बाद कहा था कि लारा का रिकॉर्ड लारा के नाम ही रहना चाहिए लेकिन बाद में उन्होंने खुलासा किया कि इस मामले पर लारा की दूसरी राय थी। मुल्डर ने कहा, 'अब चीजें पहले के मुकाबले बेहतर हुई हैं। मेरी ब्रायन लारा से भी बात हुई है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी लीगेसी बना रहा हूं और मुझे रिकॉर्ड के लिए जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड टूटने के लिए ही होते हैं और उन्होंने यह उम्मीद जताई कि मैं दोबारा उस स्थिति में आऊं कि रिकॉर्ड तोड़ पाऊं।

उनकी ओर से यह एक दिलचस्प पहलू था लेकिन मुझे अब भी यही लगता है कि मैंने सही किया क्योंकि गेम की इज्जत करना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुल्डर का 367 का नाबाद स्कोर दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है और कुल मिलाकर यह टेस्ट में पांचवां व्यक्तिगत सर्वोच्च स्कोर है।

मुल्डर ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुक्री कॉनराड ने उनसे कहा था कि महान खिलाड़ियों का रिकॉर्ड महान खिलाड़ियों के नाम ही रहने देना उचित होगा। दक्षिण अफ्रीका तीन दिन के भीतर यह टेस्ट पारी और 236 रनों से जीत गया। इसी सप्ताह क्रिस गेल ने कहा था कि मुल्डर शायद पैनिक कर गए होंगे और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास ना कर गलती की है क्योंकि ऐसे अवसर जीवन में एक बार ही आते हैं। गेल ने कहा था, 'अगर मुझे 400 तक पहुंचने का मौका मिलता तो मैं निश्चित तौर पर इसके लिए जाता। ऐसा आम तौर पर नहीं होता है।

आपको नहीं पता कि अब आपको कब तिहरा शतक जड़ने का मौका मिलेगा। और जब आपको ऐसा मौका मिलता है तो आपको इसे भुनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर आप महान खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आप कैसे बनेंगे? महान खिलाड़ियों के पास रिकॉर्ड भी होता है।

बांग्लादेश प्रीमियर लीग चुनाव के चलते पोस्टपोन होगीचैयरमैन अनाम बोले- टूर्नामेंट मई में हो सकता है, नए स्टेडियम होंगे शामिल

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग पोस्टपोन हो सकता है। बीपीएल के चेयरमैन महबूब अनाम ने कहा है कि आने वाला बीपीएल सीजन दिसंबर-जनवरी की जगह मई में कराया जा सकता है। महबूब अनाम ने यह जानकारी गुरुवार (10 जुलाई) को शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपात बैठक के बाद दी। अनाम ने कहा, यह फैसला देश में 2026 की शुरुआत में होने वाले आम चुनावों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

इससे एक दिन पहले ही चीफ एडवाइजर प्रो. मुहम्मद यूनुस ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे दिसंबर तक चुनाव की तैयारी पूरी कर लें। महबूब ने कहा, बीपीएल की तारीख चुनावों के कारण बदल सकती है। यह या तो दिसंबर से पहले होगा या फिर मई में कराए जाने की योजना है। सरकार के फैसले के बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे।

नहीं होगा एशिया कप 2025?

भारत और श्रीलंका ने किया बड़ा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। सितंबर में होने वाले एशिया कप 2025 पर संकट के बादल और ज्यादा मंडराने लगे हैं. अब इस टूर्नामेंट के रद्द होने की संभावना जताई जा रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 24 जुलाई को ढाका में होने वाली एशियाई क्रिकेट परिषद की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. रिपोर्ट के अनुसार, दोनों बोर्ड ने ये फैसला ऐसे समय लिया है, जब छह देशों के इस टूर्नामेंट के शुरू होने में दो महीने से भी कम दिन बचे हैं.

इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. 5 सितंबर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इससे पहले 24 जुलाई को ढाका में होने वाली एसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट के हिस्सा न लेने से इस टूर्नामेंट के होने पर सवालिया निशान लग रहे हैं. बीसीसीआई ने एसीसी की मीटिंग ढाका में होने पर आपत्ति जताई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी वर्तमान में एसीसी के अध्यक्ष हैं. बीसीसीआई ने हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत के बांग्लादेश दौरे को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए मना लिया था. ये दौरा अगस्त में होने वाला था, लेकिन एसीसी ने अपनी बैठक ढाका में आयोजित कर दिया, जिससे बीसीसीआई खुश नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के राजनीतिक हालत इस समय ठीक नहीं है.

5 गेंद पर 5 विकेट, आयरलैंड के गेंदबाज ने रचा इतिहास; 87 पर 5 विकेट से 88 रन पर ऑल आउट हुई विरोधी टीम

नई दिल्ली, एजेंसी। आयरलैंड के ऑलराउंडर कर्टिस कैंपर पेशेवर क्रिकेट में 5 गेंद पर 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने गुरुवार (10 जुलाई) को इंटर-प्रोविंसिल टी20 ट्रॉफी में नॉर्थ-वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ मुंस्टर रेड्स की ओर से खेलते हुए 2.3 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट लिए।

मुंस्टर रेड्स के कप्तान कैंपर ने अपने दूसरे और तीसरे ओवर में पांच विकेट लिए। इससे वॉरियर्स की टीम 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 87/5 से 88 पर ऑल आउट हो गई। पांच विकेट में से पहले विकेट जेरेड विल्सन 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए। कैंपर की स्विंग से गेंद ऑफ स्टंप पर जा लगी।

कैंपर ने हैट्रिक पूरी की

अगली गेंद पर ग्राहम ह्यूम बैकफुट पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इनस्विंगर उनके पैड पर लगी। कैंपर ने अपने अगले ओवर की शुरुआत में हैट्रिक पूरी की। 14वें ओवर की पहली गेंद पर एंडी मैकब्राइन डीप मिडविकेट की ओर स्लॉग शॉट खेलने में चूक गए।

रॉबी मिलर पहली गेंद पर कैच आउट हो गए

विकेट लेने का सिलसिला तब जारी रहा जब नंबर 10 रॉबी मिलर पहली गेंद पर कैच आउट हो गए। वह ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को मारने की कोशिश कर रहे थे।

इसके बाद कैंफर ने राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नंबर 11 पर जोश विल्सन को आउट किया।

चोट के बाद कैंफर का दूसरा मैच

उंगली की चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से बाहर होने के बाद यह कैंफर का दूसरा मैच था।

मंगलवार को लेइनस्टर लाइटनिंग के खिलाफ अपने वापसी मैच में उन्होंने 35 गेंदों पर 57 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी नहीं की थी। गुरुवार को भी उन्होंने 24 गेंदों पर 44 रन बनाए और फिर पांच विकेट लिए।

नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्यवाही तथा नशीली सामग्री के तंत्र को समाप्त करें : उप मुख्यमंत्री

नशे से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास की भी पूरी व्यवस्था करें : उप मुख्यमंत्री

रीवा संभाग में नशे के विरूद्ध अभियान में बहुत अच्छा काम हो रहा है : उप मुख्यमंत्री

रीवा। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने नशामुक्त भारत अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा संभाग में पिछले 6 महीने में नशामुक्त अभियान के तहत बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। बड़ी संख्या में नशे के व्यापार मंद लिप्त व्यक्तियों को जेल भेजने के साथ गांजा और कोरेक्स की भारी मात्रा में बरामदगी की गई है। नशा व्यक्ति के तन, मन और धन तीनों का विनाश करता है। रीवा और पूरे विन्ध्य क्षेत्र में चारों ओर हो रहा तेजी से विकास तभी सार्थक होगा जब भावी पीढ़ी को नशे से दूर रखा जाए। भावी पीढ़ी नशे की राह पर चली गई तो हर तरह का विकास बेमानी हो जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरेक्स तथा अन्य नशीले कप सिरप जहाँ पर बनाए जाते हैं वहाँ से जिले में पहुंचने और बिक्री होने तक के पूरे तंत्र पर कड़ी निगरानी रखकर कार्रवाई करें। नशे के सौदागरों को जेल में भेजने के साथ कड़ी सजा दिलाने के प्रयास करें। अपराधियों पर कार्रवाई के साथ-साथ नशीले पदार्थों के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास के भी प्रयास करें। इस कार्य में विभिन्न विभागों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आमजनों का पूरा सहयोग प्राप्त करें। नशा सामाजिक और आर्थिक बुराई होने के साथ-साथ अपराधों का भी मूल है। पूरे संभाग में नशे के विरूद्ध बड़ा जागरूकता अभियान चलाएं। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने संभाग विशेषकर रीवा जिले में नशे के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 6 महीने में दो करोड़ से अधिक राशि के नशीले कप सिरप और गांजा की जप्ती की गई है। संभाग भर में अभियान चलाकर एक दिन में ही अवैध शराब के निर्माण पर कार्रवाई करते हुए 1017 आरोपियों को गिरफ्तार कर 22 लाख रुपए की अवैध शराब जप्त की गई। नशे के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रीवा जिले में वर्ष 2023 में 176, वर्ष 2024 में 162 तथा वर्ष 2025 में अब तक 129 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आमजनता से संवाद के लिए थाना स्तर पर जनचौपाल का आयोजन करके आमजनता की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। पुलिस ने पशु तस्करों पर कार्रवाई करते हुए दो हजार से अधिक पशुओं को मुक्त कराकर विभिन्न गौशालाओं में भेजा है। पशु तस्करी में लिप्त 32 आरोपियों को जेल भेजा गया है। पुलिस ने 250 से अधिक गुमे हुए व्यक्तियों को बरामद कर उनके परिजनों को सौंपा है। पुलिस महानिरीक्षक ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही रात्रिकालीन गश्त, फरार वारंटियों की गिरफ्तारी तथा अन्य कार्यवाहियों की भी जानकारी दी। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल, श्री राजेश पाण्डेय तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर को

रीवा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर को किया जाएगा। नालसा के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे जाएंगे। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उप सचिव अनिरूद्ध जैन ने नेशनल लोक अदालत की तैयारी के लिए सर्व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

कमिश्नर आज सिंगरौली में नगर निगम के कार्यों की करेंगे समीक्षा

रीवा। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद सिंगरौली नगर निगम के निर्माण कार्यों, शासन की प्राथमिकता वाली विभिन्न योजनाओं, विभागीय गतिविधियों एवं बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक नगर निगम सभागार सिंगरौली में 12 जुलाई को सुबह 11 बजे से आयोजित की गई है। बैठक में सिंगरौली नगर निगम आयुक्त, सहायक यंत्री एवं अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे।

सड़कों में सुधार तथा स्पीड ब्रोकर बनाने का कार्य तत्काल करें : पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधीक्षक और एडीएम ने दुर्घटना संभावित स्थलों का किया निरीक्षण

रीवा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर रीवा शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह तथा एडीएम श्रीमती सपना त्रिपाठी ने रेलवे ओवर ब्रिज गोड़हर से अगडाल तक सड़क दुर्घटना के संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बायपास जंक्शन, चन्द्रलोक होटल के पास, निर्मल सिटी मोड़, एयरपोर्ट मोड़ तथा अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बायपास जंक्शन में सड़क का सुधार तत्काल कराएं। इसमें प्रयागराज मार्ग से आने वाले वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर तत्काल लगा दें। वाहनों के शहर की ओर मुड़ते समय सामने से तेज गाति से वाहन आने पर दुर्घटनाएं होती हैं। बायपास मार्ग और चोरहटा से रतहरा मार्ग में शहर के बाहरी क्षेत्र में जहाँ मुख्य सड़क पर कालोनियाँ के गेट हैं वहाँ भी स्पीड ब्रेकर बनाना आवश्यक है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन चालकों को सचेत करने के साथ-साथ सुरक्षा के सभी उपाय करें। निरीक्षण के समय एसडीएम हुजूर वैशाली जैन, एसडीओपी, प्रभारी यातायात, तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला, थाना प्रभारी चोरहटा विकास मिश्रा, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी नितिन पटेल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में नवनिर्मित ओपीडी भवन का किया निरीक्षण

रीवा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल रीवा में नवनिर्मित नवीन ओपीडी भवन का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन भवन के लोकार्पण की सभी तैयारियाँ कर लें। इसमें आवश्यक उपकरण तथा फर्नीचर लगा दें। इसके विभिन्न कक्षों को निर्धारित विभागों को कार्य करने के लिए आवंटित कर दें। नवीन ओपीडी भवन से जिला अस्पताल में आने वाले रोगियों को उपचार की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जिला चिकित्सालय में नवीन भवन के साथ 300 बिस्तर में भर्ती की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मौके पर उपस्थित कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड अनुज प्रताप सिंह ने नवीन भवन के निर्माण के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, सिविल सर्जन डॉ प्रतिभा मिश्रा, अन्य चिकित्सा अधिकारी, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

धरती आबा जन भागीदारी अभियान का आयोजन 13 जुलाई को

रीवा। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा धरती आबा जन भागीदारी अभियान का आयोजन 13 जुलाई को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस आयोजन के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल होंगे। अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले पात्र हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिये पक्के आवास देने का वरदान है : शुक्ल

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को हितलाभ का हुआ वितरण

उप मुख्यमंत्री ने ईडब्ल्यूएस आवास के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र सौंपे

रीवा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हितग्राहियों को प्रथम किश्त वितरण का कार्यक्रम नगर निगम के टाउन हाल में आयोजित किया गया। हितग्राहियों को ऋण राशि वितरण करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिये पक्के आवास देने का वरदान है। इसके माध्यम से देश में 4 करोड़ पक्के आवास लोगों को मिल चुके हैं आने वाले समय में 3 करोड़ मकान गरीबों को दिये जायेंगे। उप मुख्यमंत्री ने रीवा शहर के आवास योजना के 224 हितग्राहियों को आवास की एक लाख रूपये की प्रथम किश्त की स्वीकृति पत्र सौंपे।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश के 65 हजार से अधिक हितग्राहियों को 1626 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से हितग्राहियों को राशि का वितरण किया। कार्यक्रम का संजीव प्रसारण नगर निगम टाउन हाल में आयोजित कार्यक्रम में दिखाया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना से रीवा में एएसपी के तहत 1736 आवास तैयार किये जा चुके हैं। इसी प्रकार पूर्व में 4198 आवास पूर्ण हो गये हैं तथा 224 हितग्राहियों को प्रथम किश्त के तौर पर एक लाख रूपये की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि कोई भी गरीब बच्चे आवास में न रहे। उनकी संकल्पना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रदेश व जिले में भी गरीबों को पक्के आवास प्रदान किये जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों, युवाओं, किसानों व महिलाओं के कल्याण के लिये कृत संकल्पित है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल ने कहा कि देश व प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की मंशानुरूप पक्के गरीबों के हित में कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिये मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दिया। अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय ने कहा कि रीवा शहर में गरीबों को पक्के आवास दिलाये जा रहे हैं। जो व्यक्ति छूट गये हैं उन्हें भी आवास दिये जा रहे हैं।

जिले में अब तक 189.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज

रीवा। जिले में एक जून से अब तक 189.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। जिले में 11 जुलाई को 17.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दिन तहसील हुजूर में 20 मिलीमीटर, गुढ़ में 34 मिलीमीटर तथा सेमरिया में 36 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस संबंध में अधीक्षक भू-अभिलेख महेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक तहसील हुजूर में 212.8 मिलीमीटर, रायपुर कर्चुलियान में 131.5 मिलीमीटर, गुढ़ में 330 मिलीमीटर, सिरमौर में 232.6 मिलीमीटर, त्योंथर में 77 मिलीमीटर, सेमरिया में 211 मिलीमीटर, मनगवां में 172 मिलीमीटर तथा जवा में 147 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज गयी।

राजस्व प्रकरणों में 50 प्रतिशत से कम निराकरण पर होगी कार्यवाही

राजस्व अधिकारी नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन पर विशेष ध्यान दें : कमिश्नर

रीवा। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित संभागीय बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कानून और व्यवस्था की निगरानी के साथ राजस्व कार्यों पर विशेष ध्यान दें। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण करें। निर्धारित दिवस में राजस्व न्यायालय में अनिवार्य रूप से बैठकर प्रकरणों की सुनवाई करें। लंबित प्रकरणों में 50 प्रतिशत से कम निराकरण होने पर कार्यवाही की जाएगी। सभी एसडीएम और तहसीलदार पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से निराकरण करें। संभाग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में सिंगरौली जिले ने सबसे अच्छा प्रयास किया है। रीवा जिले में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ है। मऊगंज और सीधी जिलों के कलेक्टर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करके स्थिति में सुधार लाएं। नवगठित मऊगंज जिले में भी राजस्व प्रकरणों का निराकरण अच्छा हुआ है। आरसीएमएस पोर्टल तथा सीएम हेल्पलाइन में कोई भी जिला रैंकिंग में 30 से नीचे न जाए, इसके लिए सतत प्रयास करें। कमिश्नर ने कहा कि सीमांकन और नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण 80 प्रतिशत से अधिक होना सुनिश्चित करें। अनावश्यक पेशी देकर प्रकरण लंबित न रखें। अविवादित नामांतरण तथा बंटवारा के प्रकरण तत्काल निराकृत कराएं। सभी निराकृत प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। एसडीएम मऊगंज, त्योंथर तथा मझौली प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएं। कलेक्टर मऊगंज राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। अच्छे कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस में सम्मानित करें। राजस्व प्रकरणों के बड़ी संख्या में लंबित रहने के कारण ही संभाग में सीएम हेल्पलाइन में राजस्व विभाग में शिकायतों की संख्या अधिक है। इसमें 50 दिन से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का तत्परता से निराकरण कराएं।

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार भू राजस्व की वसूली पर भी ध्यान दें। आरआरसी की वसूली के लिए भी अभियान चलाएं।

रीवा संभाग में अब तक 357 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

रीवा। रीवा संभाग में एक जून से अब तक 357 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। संभाग में 11 जुलाई को 46 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक 78 मिलीमीटर वर्षा मैहर जिले में दर्ज की गई। संभाग में एक जून से अब तक सर्वाधिक 537 मिलीमीटर वर्षा मऊगंज जिले में दर्ज की गई है। संभाग में इस अवधि में रीवा जिले में 189.2 मिलीमीटर, सतना में 285.6 मिलीमीटर, मैहर में 363.4 मिलीमीटर, सीधी में 418.9 मिलीमीटर तथा सिंगरौली जिले में 353 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में संभाग में 151 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। संभाग में सिंचाई के प्रमुख स्त्रोत बाणसागर बांध में 11 जुलाई को सुबह 8 बजे तक जल स्तर 339 मीटर तक पहुंच गया है। गत वर्ष 11 जुलाई तक इसका जल स्तर 332.31 मीटर पर था। बांध में 74 प्रतिशत जल भराव हो गया है।

फीडर सेपरेशन और नए विद्युत सब स्टेशन का निर्माण तय समय सीमा में करें

जाँच के नाम पर ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को परेशान न करें : उप मुख्यमंत्री

रीवा। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में कहा कि विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए कई परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। फीडर सेपरेशन तथा नए विद्युत सब स्टेशन के निर्माण का कार्य तय समय सीमा में पूरा करें। शहर में पीटीएस चौराहा तथा चोरहटा में दो नए सब स्टेशन का निर्माण पूरा होने से विद्युत व्यवस्था बेहतर हुई है। शहर में कई स्थानों में विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन्हें तत्काल बदलें। इनसे कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। शहर में बिजली की ट्रिपिंग को रोकने के लिए भी प्रभावी उपाय करें। कई बिजली उपभोक्तओं द्वारा मीटर की जाँच के नाम पर परेशान करने की शिकायतें की गई हैं। जाँच के नाम पर ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को परेशान न करें। यदि कोई व्यक्ति बिजली की चोरी कर रहा है तो सही मूल्यांकन करके ही जुर्माना लगाएं। ईमानदारी से बिजली का बिल भुगतान करने वालों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन सिक्स लेन बायपास रोड से बिजली लाइनों की तत्काल शिफ्टिंग कराएं। प्रस्तावित सड़क में भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित करें। बैठक में अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रमा पाण्डेय ने बताया कि खराब विद्युत पोल बदलने के लिए एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। इसका कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है। खराब ट्रांसफार्मर तय समय सीमा में बदले जा रहे हैं। संभाग के सभी डिपो में पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं।

हिनौती गौधाम को आदर्श गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा : शुक्ल

रीवा। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में हिनौती गौधाम के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिनौती गौधाम को आदर्श गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। इसमें 25 हजार से अधिक गौवंश को आश्रय मिलेगा। इसके बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूरा कराकर गौवंश को सुरक्षित करें। इसके परिसर में उपयुक्त स्थलों पर वृक्षारोपण भी कराएं। गौशाला के स्वागत द्वार और सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा कराएं। गौशाला में रह रहे निराश्रित गौवंश के भोजन, पानी तथा उपचार की समुचित व्यवस्था करें। गौशाला के विकास के लिए मिलकर प्रयास करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने ग्रामीण यांत्रिकी विभाग तथा ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी दी।

राजस्व अधिकारी रेलवे परियोजना के निर्माण कार्यों की बाधाओं का समाधान करें : कमिश्नर

रीवा। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन में सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में भू अर्जन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। न्यायालयीन प्रकरण अथवा अन्य कारणों से जो प्रकरण शेष हैं उनका भी निराकरण तेजी से करें। सभी कलेक्टर भू अर्जन प्रकरणों के निराकरण की हर सप्ताह समीक्षा करें। शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भू अर्जन की कार्यवाही पूरी करें। भू अर्जन करते समय विस्थापित परिवारों के हितों का भी पूरा ध्यान रखें। निर्माण कार्यों के लिए जमीन प्राप्त होने के बाद रेलवे तत्काल उस पर निर्माण कार्य शुरू करे। निर्माण कार्य में देरी होने से कई तरह की कठिनाईयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। रीवा से बघवार तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। सीधी जिले में शेष क्षेत्र में लाइन बिछाने का कार्य तेजी से करें।

कमिश्नर ने कहा कि मुआवजा वितरण के बाद भी यदि निर्माण कार्यों में कोई बाधा डालता है तो राजस्व अधिकारी मौके पर जाकर उसका निराकरण करें। रेलवे के अधिकारी तथा राजस्व अधिकारी समन्वय के साथ परियोजना के निर्माण कार्यों को पूरा कराएं। सीधी जिले के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज हैं उन्हें लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करने का प्रयास करें। भू अर्जन से प्रभावितों से सतत संपर्क करके लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। राजस्व अधिकारियों ने भू अर्जन में बहुत अच्छा कार्य किया है। रीवा से देवसर तक रेलवे लाइन निर्माण की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। रेलवे तेजी से निर्माण कार्य पूरे करे।

बहनों के हौसले की मजबूत डोर खुशियां हर ओर

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा

1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को

26 वीं किस्त के

₹ 1543.16 करोड़

56.74 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को ₹ 340 करोड़

30 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रीफिलिंग राशि ₹46.34 करोड़ का सिंगल क्लिक से अंतरण

अपराह्न 2:30 बजे | ग्राम पंचायत नलवा, जिला उज्जैन

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

राज्य स्तरीय निषादराज सम्मेलन

मछुआ कल्याण के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं हितलाभ वितरण

अपराह्न 1:00 बजे । मुक्ताकाशी मंच, कालिदास अकादमी, उज्जैन

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

12 जुलाई 2025

सीधा प्रसारण webcast.gov.in/mp/cmevents @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhypradesh @jansamparkMP JansamparkMP

D-11064/25

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक एवं मुद्रक राजेन्द्र तिवारी द्वारा एस आर के प्रिंटिंग प्रेस विवि रोड खुटेही रीवा से मुद्रित कर जीडीसी के सामने उत्तरी करौंदिया सीधी से प्रकाशित। संपादक-राजेन्द्र तिवारी , आर.एन.आई नं. 47589/88 , डाक पंजीयन : **MP/SDL/DN/-30/2015-17,** दूरभाष : 09424315633,7389444833